RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 02, अंक 12 मासिक पत्रिका
25 दिसम्बर 2023

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

मोहन यादव को सौंपी राज्य की कमान...

सामने बड़ी चुनौतियां पूरे करने होंगे वादे

वर्ष 2024
...दिल्ली से लेकर अनुच्छेद 370 पर भी आया फैसला

एसबीआई रिपोर्ट
लाडली बहना योजना जीत में दिलाई अहम भूमिका

HAPPY

New Year!

2024

हमारा देश हमारा
अभिमान परिवार की ओर
से नववर्ष की...

हार्दिक शुभकामनाएं

हमारा देश
हमाराअभिमान

25 दिसम्बर 2023

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडो कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	.....	02
शुभाशीष	.....	03
कवर स्टोरी	.....	04-05
देश	.....	06-07
विदेश	.....	08
प्रदेश	.....	09
विदेश	.....	10
देश-प्रदेश	.....	11
देश	.....	16-17
मप्र-छग	.....	18
देश	.....	19
देश	.....	20-21
देश	.....	22
प्रदेश	.....	23
देश	.....	27
विदेश	.....	32
देश	.....	33
देश-दुनिया	.....	34
वित्त	.....	35
सरहद पार	.....	37
शिक्षा	.....	38
सेहत	.....	40-41
धर्म	.....	44-45
मौसम	.....	47
खेल	.....	47
ग्लैमर	.....	48

48

तृप्ति डिमरी एक्टिंग के साथ घुमक्कड़ भी

संपादकीय

राजस्थान कांग्रेस में समाप्त हुआ अशोक गहलोत व पायलट युग

2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री व सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था। तभी से गहलोत व पायलट के बीच खींचतान प्रारंभ हो गई थी। राजस्थान में दोनों बड़े नेता के अलग-अलग दो गुट बन गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों ही नेताओं को कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान की राजनीति से बाहर भेज दिया है। अब राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में नए लोगों को आगे लाने की कवायद प्रारंभ हो गई है। पिछले लंबे समय से राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति अशोक गहलोत व सचिन पायलट के इर्द-गिर्द ही घूम रही थी। दोनों नेताओं में चल रही आपसी खींचतान के चलते राजस्थान में कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों की अवादत के चलते ही राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से भी बाहर हो चुकी है । 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री व सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था। तभी से गहलोत व पायलट के बीच खींचतान प्रारंभ हो गई थी। राजस्थान में दोनों बड़े नेता के अलग-अलग दो गुट बन गए थे। दोनों नेताओं की खींचतान के चलते स्थिति यहां तक खराब हो गई थी कि 2020 में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर अपने समर्थक विधायकों को लेकर गुड़गांव चले गए थे। उस समय सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत को विधायकों की होटलों में बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी। करीबन दो महीने तक चली आपसी खींचतान के बाद कांग्रेस आलाकमान के प्रयासों से कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच शांति स्थापित हो पायी थी। मगर सचिन पायलट को बगावत के चलते उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा था। वही उनके समर्थक कई मंत्रियों को भी पदो से हटा दिया गया था।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

वर्ष 2023 : भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की...

दुनिया के कई हिस्सों में व्याप्त अशांति के बावजूद भारत ने वर्ष 2023 में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। यह न केवल दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अनुमान है कि यदि पहले नहीं, तो 2030 तक यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत ने 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसके तहत 60 विभिन्न जगहों पर 250 से ज्यादा बैठकें हुईं, अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता मिली और पहले ही दिन दुनिया भर के नेताओं ने दिल्ली घोषणापत्र पर सहमति व्यक्त की। जी-20 की अध्यक्षता समाप्त होने से पहले पहली बार भारत ने एक आभासी शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड, जी-7, आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भागीदारी की और आभासी रुप से शंघाई सहयोग संगठन की एक एवं वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ के दो शिखर सम्मेलनों की मेजबानी की। उन्होंने अमेरिका की सफल राजकीय यात्रा की और अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत संतुष्ट हो सकता है कि उसकी ऊर्जा प्रणाली में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी 43 फीसदी (172 गीगावॉट) से अधिक हो गई है और वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता 45 फीसदी कम हो जाएगी, जैसा कि ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में वादा किया गया था। मालदीव में नई सरकार का नेतृत्व मोहम्मद मुइज्जू कर रहे हैं, जो चीन समर्थक हैं। उन्होंने आधिकारिक रुप से भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने और अपना हेलिकॉप्टर वापस लेने के लिए कहा है। भारत को इस छोटे, मगर रणनीतिक रुप से महत्वपूर्ण पड़ोसी से सावधानीपूर्वक निपटना होगा।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

मोहन यादव को सौंपी राज्य की कमान...

सामने बड़ी चुनौतियां पूरे करने होंगे वादे

- प्रदेश में शिवराज सिंह का लंबा कार्यकाल खत्म हो गया है। इस चुनाव में भाजपा ने जबर्दस्त जीत हासिल की थी।

- इसके बाद पार्टी की ओर से मोहन यादव को आगे किया। विधायक दल की बैठक हुई। मोहन यादव अब प्रदेश के नए सीएम बन गए।

मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव अपने बेटे को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन यह माता और बाबा महाकाल का आशीर्वाद है।

मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि यह केवल भाजपा पार्टी ही है जो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मैं राज्य की विकास यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। मोहन यादव के लिए राज्य में कई बड़ी जिम्मेदारियां सामने हैं। भाजपा के वादों के पूरा करने में उन्हें तत्काल कदम उठाने होंगे। कुछ महीनें में ही 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं।

इसके अलावा उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी समन्वय बना के रखना होगा। राज्य के कई बड़े नेता राज्य में हैं जो उनसे सीनियर भी हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधायक दल के नए नेता के तौर पर मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं और ऐसे कार्यकर्ता (मोहन यादव) को चुनने के लिए आभार व्यक्त करता हूं जो विचारधारा के प्रति समर्पित हैं और अपनी कड़ी मेहनत से इसके लिए काम करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है।

मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव अपने बेटे को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन यह माता और बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। मोहन यादव को लेकर उनकी बहन ने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। वह 1984 से भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। वह जब भी उज्जैन आते थे, तो महाकाल की पूजा करने जाते थे।

मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी ने कहा कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। हां, उनका नाम चल रहा था लेकिन हमें ठीक से पता नहीं था। भगवान ने उन्हें उनकी मेहनत का फल दिया है। यादव, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में नहीं देखा गया था, को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का करीबी माना जाता है। वह तीन बार के विधायक और एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं। ओबीसी मप्र की आबादी का 48 प्रतिशत से अधिक हैं। वह पहली बार 2013 में उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए। इसके बाद 2018 और फिर 2023 में विधानसभा सीट बरकरार रखी।

वादों को पूरा करने की चुनौती : मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से लोक लुभावने वादे किए गए थे जिसे लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराना, गरीब परिवार की बच्चियों की 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त, हर महीने 100 यूनिट तक की बिजली सिर्फ 100 में, लाडली बहन योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, आने वाले समय में से 3000 तक करने का वादा किया गया है। किसान सम्मान के तहत 12000 देने की बात कही गई है। वहीं गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल और चावल की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का भी वादा है।

मोहन यादव का राजनीतिक करियर 2013 में विधायक के रूप में उनके पहले चुनाव के साथ शुरू हुआ, और वह 2018 के मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में फिर से चुने गए। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में यादव का प्रभाव तब और मजबूत हो गया जब उन्होंने 2 जुलाई, 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे मोहन यादव कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अपने राजनीतिक प्रयासों के अलावा, उन्हें एक व्यवसायी के रूप में भी जाना जाता है।

इन 'सुप्रीम' आदेशों की वजह से याद किया जाएगा साल

...दिल्ली से लेकर अनुच्छेद 370 पर भी आया फैसला

साल 2023 अब खत्म होने वाला है। इस साल भारत के हिस्से में न केवल सेना अंतरिक्ष, विज्ञान, मेडिकल से जुडी उपलब्धियां आई वरन कानूनी जगत में भी देश की सर्वोच्च अदालत ने कई ऐसे फैसले दिए जिससे सालों से चल रहे विवाद समाप्त हो गए और जिनकी खूब चर्चा हुई। इनमें चाहें हम धारा 370 की संवैधानिक वैधता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें या जल्लीकट्टू पर आए फैसले की या फिर समलैंगिक विवाह को लेकर आए फैसले की। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को निपटाया। आज हम आपको बताएंगे कि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कौन-कौन से बड़े फैसले दिए और कितने मामले निपटाए।

देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट : देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित की गई थी। शीर्ष अदालत के पास कानूनों की व्याख्या करने और उन पर निर्णय देने की शक्ति है। इतना ही नहीं, इसके पास उच्च न्यायालयों और अन्य सभी न्यायालयों के निर्णयों की भी समीक्षा करने की भी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है।

इन महत्वपूर्ण मामलों में आया 'सुप्रीम' फैसला : इस साल कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को हमेशा याद रखा जाएगा, वह जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी देने वाले ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया। शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है।

इसके अलावा, अक्तूबर माह में शीर्ष कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े के विवाह पर भी ऐतिहासिक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा था कि इस तरह की अनुमति सिर्फ संसद के जरिए कानून बनाकर ही दी जा सकती है। इस साल शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी बड़ा और अहम फैसला सुनाया था। शीर्ष कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मार्च में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल के जरिए की जाएगी। इस पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष (सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) को शामिल किया जाएगा। इस साल तमिलनाडु के पारंपरिक जल्लीकट्टू खेल को अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया था। मई में सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने इसे कानूनन वैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार के नए कानून में पशु क्रूरता के हर विषय को ध्यान में रखा गया है।

इसके साथ ही इस साल सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर भी अहम फैसला दिया। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में शीर्ष कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने के अनिवार्य वेटिंग पीरियड को खत्म कर दिया था। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि अगर पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश न बची हो, ऐसे में अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए तलाक को तत्काल मंजूरी दे सकता है।

इसके अलावा, शीर्ष कोर्ट ने साल 2023 में मुद्रांकित दस्तावेजों और उनकी स्वीकार्यता से संबंधित मध्यस्थता मामले, सामान्य लाइसेंस पर भारी मोटर वाहन चलाने, सेवाओं पर नियंत्रण पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद का निपटारा, महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के दोनों गुटों जैसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर विधिवत सुनवाई की और फैसले भी सुनाए गए।

लंबित मामलों को लेकर उठाए बड़े कदम

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर अक्सर चिंता जाहिर की जाती रही है। लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में भी बड़े कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में अभूतपूर्व 52,191 मामलों का निपटारा किया है। ये साल 2017 में ICMIS (इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) लागू होने के बाद से संख्या की दृष्टि से निपटान सबसे अधिक है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2023 से 15 दिसंबर, 2023 तक 52191 मामलों का निपटारा किया। इनमें 45,642 विविध मामले और लगभग 6,549 नियमित मामले शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक,वर्ष 2023 में कुल 49,191 मामले पंजीकृत किए गए। वहीं, इसकी तुलना में निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या 3000 ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि साल 2017 में ICMIS (इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) लागू होने के बाद से इस साल संख्यात्मक रूप से सबसे ज्यादा मामले निपटाए गए हैं। इस साल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामलों को दाखिल करने और सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक समय-सीमा को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव करते हुए मामले के सत्यापन के बाद सूचीबद्ध होने से लेकर दाखिल करने तक का समय 10 दिनों से घटाकर 7 से 5 दिन कर दिया।

पूर्व डब्ल्यूएचओ प्रमुख वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने कहा- नया वेरिएंट चिंताजनक नहीं

देश में एक बार फिर कोरोना बढ़ता जा रहा है। कोरोना का नया सब वेरिएंट जेएन-1 चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि फिलहाल कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह खतरनाक नहीं हैं। यह चिंता का विषय नहीं है। हालांकि, स्वामीनाथन का कहना है कि सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूरी है। लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। बता दें, स्वामीनाथन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की प्रमुख भी रह चुकी हैं।

हवादार क्षेत्रों में रहें

एक साक्षात्कार में स्वामीनाथन ने बताया कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सुझाव देने के लिए फिलहाल कोई डाटा नहीं है। हमें सिर्फ सामान्य बचाव उपाय की आवश्यकता है। हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लोगों को बिना मास्क के कम वेंटिलेशन वाली जगह में रहने से बचना चाहिए। आप ऐसे किसी क्षेत्र में हैं तो मास्क जरूर पहने। किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से थोड़ा बचें। खुली जगह में रहने की कोशिश करें। अगर बुखार या सांस फूलने जैसी कोई भी समस्या होती है तो अस्पताल जरूर जाएं। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह ध्यान देना होगा कि अभी सर्दी का मौसम है। हमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। भारत में अब तक 21 मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों में फिर से घबराहट हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताया है कि वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर जेएन-1 का जोखिम कम है।

हल्के में न लें खांसी-जुकाम

द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के निदेशक डॉ. ईश्वर सिंह का कहना है कि इस मौसम में खांसी-जुकाम होना आम बात हैं, लेकिन कोरोना के बदले स्वरूप के आने में बाद इसे हल्के में नहीं ले सकते। यदि किसी मरीज को खांसी-जुकाम लंबे समय से है तो उसे कोरोना की जांच करवानी चाहिए। ऐसे मरीजों में कोरोना के मामले मिल सकते हैं। हालांकि, अभी तक आए मामलों में यह ज्यादा गंभीर नहीं पाया गया है, लेकिन बचाव के लिए सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है।

नियमों का पालन करें

- मास्क पहनें
- अपने हाथों को बार-बार साफ करें
- सामाजिक दूरी बनाएं

इन लोगों को ज्यादा खतरा

- बुजुर्ग
- बच्चे
- मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस के मरीज
- कैंसर, दिल व अन्य रोगों से बीमार लोग
- कोरोना के शुरुआती लक्षण
- लगातार बुखार रहना
- सूखी खांसी
- थकान
- सांस लेने में तकलीफ
- नाक बहना
- गले में खराश
- नाक बंद होना

घटिया दवाओं को लेकर आप मुख्यालय के पास भाजपा का प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बुधवार को एक और नमूना जांच में फेल हो गया। सचदेवा ने कहा, आज एक और नमूने की रिपोर्ट आई है और वह भी नकली पाई गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता मानक परीक्षण में विफल रही दवाओं की आपूर्ति को लेकर बुधवार को यहां आम आदमी पार्टी (आप) मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बुधवार को एक और नमूना जांच में फेल हो गया। सचदेवा ने कहा, आज एक और नमूने की रिपोर्ट आई है और वह भी नकली पाई गई है। जिन दवाओं के नमूने नकली पाए गए थे, उनका टेंडर खत्म हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ नारे भी लगाये। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां भी ले रखी थीं। सचदेवा के अलावा दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद हर्षवर्धन, मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी भी इस मौके पर मौजूद थे।

पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की थी और बैरिकेड्स लगाए थे। आप ने आरोप लगाया कि भाजपा दवा के नमूने को नकली बताकर सफेद झूठ फैला रही है। आप ने एक बयान में कहा, ''मूल रूप से भाजपा द्वारा साझा की जा रही जांचरिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें सभी वास्तविक सामग्री (साल्ट फॉर्मूलेशन) हैं। केवल एक चीज जो मानक के अनुरूप नहीं है वह इस दवा का 'डिजॉल्यूशन' (घुलना)।

आम आदमी की में इसका मूल रूप से मतलब है कि एक मानक दवा को शरीर में घुलने में 30 सेकंड लगते हैं जबकि इस नमूने को शरीर में घुलने में 40 सेकंड लग सकते हैं।

लाडली बहना योजना जीत में दिलाई अहम भूमिका-एसबीआई रिपोर्ट

महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण और सुरक्षा जो भारत की आबादी का 67.7% हिस्सा हैं। एक सुरक्षित वातावरण में उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना देश के सतत और न्यायसंगत विकास और परिवर्तनकारी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना की चर्चा सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में होती है। नए मुख्यमंत्री के आने के बाद से ही महिलाओं में ये दुविधा है कि ये योजना बंद की जा सकती है, जिसकी चिंता प्रदेश की महिलाओं को सता रही है। ये योजना काफी लोकप्रिय है, जिसे जारी रखने का दबाव नए मुख्यमंत्री पर भी होगा। इस योजना के जारी रहने और बंद होने की दुविधा के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने नई रिपोर्ट साझा की है।

भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक विभाग द्वारा जारी एक विशेष शोध रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का विश्लेषण किया गया है। इस योजना को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि ये योजना कई पारंपरिक सीमाओं तो तोड़ते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। लाडली बहना योजना के विश्लेषण की रिपोर्ट 'महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास के लिए अनिवार्य शर्तः कैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने सीमाओं को पार किया'। इस विश्लेषण में महिला सशक्तिकरण के कई पहलुओं की जांच की गई है। उनकी भूमिका पर गौर किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 28 जनवरी 2023 को राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' के कार्यान्वयन की घोषणा की थी, जिससे श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी को बढ़ाना था। इस योजना के तहत हर पात्र महिला को उसके आधार से जुड़े डीबीटी सक्षम बैंक खाते में प्रति माह 1,250 रुपये (पहलेः 1000 रुपये) का भुगतान होता है। इसका मतलब है कि 21-60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 15,000 रुपये की वार्षिक राशि जमा की जाएगी। रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि यह राशि धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह तक पहुंचेगी।

इस योजना के कार्यान्वयन से ना सिर्फ महिलाओं और उन पर निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार दिखाई देगा, बल्कि महिलाएं अपनी प्राथमिकता के मुताबिक खर्च करने के लिए आर्थिक रूप से पहले से अधिक स्वतंत्र बनेंगी। महिलाएं स्वरोजगार करनेके साथ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर आजीविका के साधन जुटाएंगी। पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता भी उनकी बढ़ सकेगी। एसबीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में कुल पात्र महिलाएं 1.25 करोड़ हैं। इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत सरकार ने 2,418 करोड़ रुपये वितरित किये हैं और इसके और बढ़ने की उम्मीद है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि लाडली बहना योजना ने 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि की।

हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका के संरक्षक एवं अखिल भारती हिंदू सेवादल के अध्यक्ष भाई श्री मनोज भारद्वाज जी के पिताजी श्री भगवानदास भारद्वाज जी का स्वर्गवास 19दिसंबर 2023को हो गया । उनके स्वर्गवास पर मेरी एवं पत्रिका के समस्त परिवार की ओर से सादर सिधांजलि प्रकट करते है। तथा भगवान बाबूजी जी आत्मा को शांति प्रदान करे।

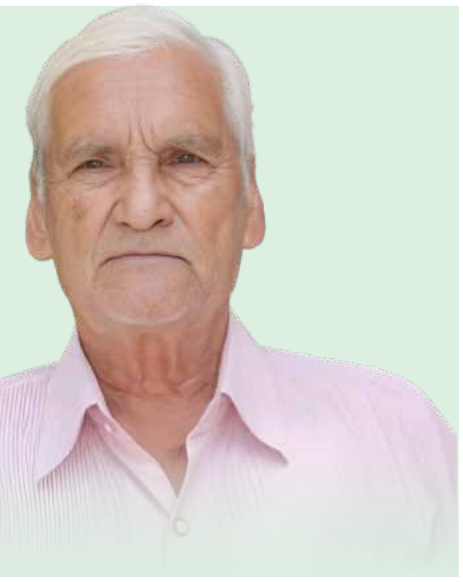

शत शत नमन्

राजस्थान में भाजपा नेता एवं हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका के वरिष्ठ सन रक्षक लोकेश चतुर्वेदी
राजस्थान का भाजपा की भारी जीत पर जगह जगह हुआ स्वागत।

डबरा निवासी हर्षित जैन पुत्र सतेंद्र कुमार जैन के सी बी सी क्लास 10 मै90 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होने पर
आगरा में प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया।

अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को चीन के लहसुन से खतरा

चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। दोनों देश एक-दूसरे की कंपनियों पर सख्ती करने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। इस बीच चीन का लहसुन भी अमेरिका के लिए खतरा बनकर उभरा है।

दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ समय से घमासान चल रहा है। दोनों देशों के बीच एकदूसरे की कंपनियों पर तरह-तरह की पाबंदियां लगाने की होड़ चल रही है। इस बीच अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को चीन के लहसुन से खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के एक सीनेटर ने सरकार से चीन से आयात होने वाले लहसुन से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कराने की मांग की है। रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट ने इस बारे में कॉमर्स मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि चीन के लहसुन का इस्तेमाल सेफ नहीं है क्योंकि इसे उत्पादन की प्रक्रिया साफ-सुथरी नहीं है।

चीन दुनिया में लहसुन का सबसे बड़ा निर्यातक है जबकि अमेरिका इसके बड़ा उपभोक्ता है। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह अपनी लहसुन को लागत से कम कीमत पर अमेरिकी बाजार में डंप कर रहा है। 1990 के दशक से ही अमेरिका ने अपने किसानों को बचाने के लिए चीन के आयात पर भारी टैक्स लगा रखा है। 2019 में डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस टैरिफ को और बढ़ा दिया गया था। अपनी चिट्ठी में सीनेटर स्कॉट ने कहा है कि चीन के लहसुन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है।

क्यों है जांच की जरूरत

उन्होंने कहा कि कई ऑनलाइन वीडियो, कुकिंग ब्लॉग्स और डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया है कि चीन में लहसुन कैसे उगाया जाता है। कई बात को इसे सीवेज में उगाया जाता है। स्कॉट ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से इस बारे में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चीन से आने वाले हर तरह के लहसुन की गहराई से जांच करने की जरूरत है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक ऐसी एमरजेंसी है जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ और आर्थिक सुरक्षा को खतरा है।

लहसुन पर दाग नहीं तो मत खरीदें

अगर आपको चीन के नकली लहसुन से बचाना है और भारत में उत्पादित हो रहे असली लहसुन की पहचान करनी है तो इसका तरीका बहुत आसान है. बाजार में बिक रहे नकली लहसुन सफेद होते हैं। इनमें कोई दाग-धब्बे नजर नहीं आएंगे. इनकी पहचान करने के लिए आप लहसुन को पलट कर देखें. अगर इसके निचले हिस्से में दाग नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये असली हैं. अगर ये पीछे बिल्कुल सफेद हैं तो वे चीनी जहरीला नकली लहसुन है।

नकली लहसुन के दावे पर जांच

सीनेटर स्कॉट ने लहसुन के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी विस्तार से बताया है. हालांकि फिलहाल इसे साबित नहीं किया जा सका है. क्यूबेक में मैकगिल विश्वविद्यालय में विज्ञान और समाज कार्यालय, का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चीन में लहसुन उगाने के लिए नाली के पानी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है।

ब्राजील की राष्ट्रपति का अकाउंट हैक

अकाउंट हैक हुआ तो भड़कीं ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी, मस्क ने कसा तंज तो दिया करारा जवाब, पढ़ें

57 वर्षीय रोसांगेला सिल्वा का एक्स खाता 11 दिसंबर को हैक किया गया था। उनके खाते से उनका और उनके पति राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का मजाक उड़ाते हुए कई अपमानजनक पोस्ट किए गए थे। ब्राजील की प्रथम महिला और राष्ट्रपति लूला सिल्वा की पत्नी रोसांगेला 'जांजा' लूला दा सिल्वा और दिग्गज कारोबारी एलन मस्क के बीच जुबानी जंग छिड़ती दिख रही है। जांजा ने मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर केस करने की धमकी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते हफ्ते उनका एक्स का खाता हैक हो गया था। इस दौरान उनके खाते से हैकरों ने महिला विरोधी संदेश पोस्ट किए थे। उनका कहना है कि इस प्लेटफॉर्म के मालिक ने इस घटना पर भी अपनी आदत का परिचय दिया है।

11 दिसंबर को हुआ था हैक : 57 वर्षीय रोसांगेला सिल्वा का एक्स खाता 11 दिसंबर को हैक किया गया था। उनके खाते से उनका और उनके पति राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का मजाक उड़ाते हुए कई अपमानजनक पोस्ट किए गए थे। ब्राजील पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। जांजा ने कहा कि मस्क इस घटना को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह केवल मेरे साथ ही नहीं हुआ है बल्कि हर दिन हजारों महिलाओं के साथ होता है।

12 लाख फॉलोअर्स : रोसांगेला सिल्वा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 12 लाख फॉलोअर्स हैं। सिल्वा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था, 'मैं रोजाना जिन घृणित और अपमानजनक हमलों का सामना करती हूं, वे एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। मेरा एक्स खाता हैक कर लिया गया है। खाते से मेरे खिलाफ महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण और हिंसक संदेश पोस्ट किए गए।'

कंपनी पर केस करने की धमकी : जांजा ने इस सप्ताह की शुरुआत में कंपनी पर मुकदमा करने की धमकी दी। उन्होंने दावा किया कि खाते से पोस्ट हटाने और फिर से पहुंच हासिल करने में मदद करने के अनुरोधों को नजरअंदाज किया गया। कई अनुरोधों के बावजूद ढिलाई की गई।

एलन मस्क का जवाब: सिल्वा के आरोप पर एलन मस्क ने बुधवार को कहा कि इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कानूनी खतरे का जिक्र करने वाले पोस्ट पर कहा, 'यह समझ नहीं आ रहा है कि किसी के द्वारा उनके पासवर्ड का पता लगाना हमारी जिम्मेदारी कैसे हो गई।'

सागर में रिश्वतखोर बाबू को सजा..

प्रभारी समिति प्रबंधक के पद पर बहाली का आदेश पक्ष में कराने के एवज में मांगी थी 50 हजार की रिश्वत

सागर में प्रभारी समिति प्रबंधक के पद पर बहाली का आदेश पक्ष में कराने के एवज में रिश्वत लेने वाले आरोपी प्रकाश कोरी को अदालत ने 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 5 नवंबर 2019 को आवेदक रामअवतार पटना ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि सेवा सहकारी समिति लखेरी जिला छतरपुर में पदस्थ विक्रेता, वर्तमान प्रभारी समिति प्रबंधक रामदयाल पटेल ने 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त पंजीयक सहकारिता सागर संभाग के न्यायालय में उसके प्रभारी समिति प्रबंधक के पद पर बहाली के आदेश के खिलाफ अपील की थी। मामले में संयुक्त पंजीयक सहकारिता कार्यालय सागर में शीघ्रलेखक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ आरोपी प्रकाश कोरी ने उक्त अपील में उसके पक्ष में आदेश पारित कराने के एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की है। वह आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता। बल्कि रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है। शिकायत मिलते ही लोकायुक्त ने जांच कराई।

जांच में शिकायत सही पाई गई। जिस पर टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना की गई। टीम ने आवेदक को रिश्वत की राशि लेकर आरोपी के पास भेजा। जैसे ही आवेदक ने रिश्वत की राशि आरोपी को दी, वैसे ही लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर प्रकाश कोरी को रंगेहाथ रिश्वत की राशि के साथ धरदबोचा। मामले में लोकायुक्त ने आरोपी प्रकाश के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया।

न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी प्रकाश कोरी को दोषी पाया और फैसला सुनाते हुए 4 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।

कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर अनुराग ठाकुर का कटाक्ष

बोले- 1984 के पीड़ितों को नहीं मिला न्याय

कांग्रेस की 'भारत न्याय यात्रा' पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने अपने शासनकाल में 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं दिया, अब वो किसे न्याय देने की बात कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'भारत जोड़ो यात्रा' के बाद अब 'भारत न्याय यात्रा' की शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस के एलान के बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा की घोषणा पर तीखा तंज कसा है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में विफल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को भारत न्याय यात्रा पर कहा कि कांग्रेस 1984 सिख दंगों के पीड़ितों को ही न्याय दिलाने में विफल रही थी, इसका मुख्य कारण यह कि उनके साथ टुकड़े-टुकड़े गैंग खड़ा है। बता दें भारत न्याय यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। यह यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 67 दिनों में मणिपुर से मुंबई तक, 67 दिनों में पूर्व से पश्चिम तक 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के भारत न्याय पर पूछे गए सवाल पर अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग अपने शासन के दौरान 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय नहीं दिला सके, वे किसी को कैसे न्याय दिला सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जिनके साथ टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य हो और जो लोग जाति और क्षेत्र के आधार पर विभाजन करने की कोशिश करते है, वे कैसे न्याय देंगे।

वहीं मोदी सरकार की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह पीएम मोदी की सरकार ही थी जिन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी जांच का गठन किया था। देश की जनता कांग्रेस के असली चेहरे को पहचान चुकी हैं। वे भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, उन्होंने सदैव हिंदुओं और सनातन धर्म का अपमान ही किया है। इतना ही नहीं उनके नेता और सहयोगी दलों ने सनातन धर्म को लेकर कई बयान दे रहे हैं। बता दें 2016 को जेएनयू में हुए उपद्रव के बाद टुकड़े-टुकड़े गैंग शब्द अस्तित्व में आया। जिसके बाद से भाजपा द्वारा राष्ट्र विरोधी आरोप लगाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा के ईवीएम को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए ठाकुर ने कहा कि हाल में हुए विधानसभा चुनावों में मिली पराजय के बाद कांग्रेस हार का कारण के ढूंढने के बजाय बहाने तलाश रही है। ठाकुर ने कहा, जब वे एक राज्य में जीत गए तो क्या वहां अलग ईवीएम है। अब तो जनता भी उन पर हंसती है। ये वही लोग हैं जो दावा करते थे कि उन्होंने कंप्यूटर खरीदा है और आज वे तकनीक का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि पित्रोदा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सदस्यों से ईवीएम को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव देश की नियति तय करेगा।

राहुल गांधी का लक्ष्य देश को एकजुट रखना नहीं: अठावले

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'भारत न्याय' यात्रा पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो' यात्रा की, लेकिन उनका लक्ष्य देश को 'एकजुट' करना नहीं बल्कि तोड़ना था। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने का काम नहीं किया। अब राहुल गांधी इस दिशा में चल रहे हैं।

महाकाल मंदिर से लिए गए सैंपल

की जाएगी जांच, कहीं पूजा सामग्री शिवलिंग को नुकसान तो नहीं हो रहा

टीम ने निरीक्षण किया और मंदिर परिसर से पूजन सामग्री के सैंपल इकट्ठे किए है। निरीक्षण के दौरान टीम ने मंदिर समिति को किसी तरह की हिदायत नहीं दी है। इस संबंध में जीएसआई भोपाल ऑफिस के डायरेक्टर आरएस शर्मा का कहना है कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और महाकालेश्वर शिवलिंग की जांच में सबसे पहले दरारों का अध्ययन किया गया है।

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग का लगातार क्षरण (नुकसान) हो रहा है। यही कारण है कि आम जनता और भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश बंद किया गया है। इसी बीच जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने भी इस शिवलिंग की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को करनी है, जिसने मंदिर परिसर का जायजा लिया है।

टीम ने निरीक्षण किया और मंदिर परिसर से पूजन सामग्री के सैंपल इकट्ठे किए है। निरीक्षण के दौरान टीम ने मंदिर समिति को किसी तरह की हिदायत नहीं दी है। इस संबंध में जीएसआई भोपाल ऑफिस के डायरेक्टर आरएस शर्मा का कहना है कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और महाकालेश्वर शिवलिंग की जांच में सबसे पहले दरारों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट का मिलान पिछली रिपोर्ट से किया जाएगा। जांच करने के लिए मशीनों से टेस्ट भी किए गए है।

टीम की मानें तो टीम ने शिवलिंग पर चढ़ाई गई पूजा सामग्री, फूल, श्रृंगार सामग्री, दही, भांग, जल आदि के सैंपल को इकट्ठा किया है। आरओ के जल द्वारा होने वाले अभिषेक का भी सैंपल लिया गया है। अब इन सभी सैंपल की जांच लैबोरेट्री में की जाएगी। लैब में टेस्ट होने के बाद इसकी रिपोर्ट जीएसआई को सौंपी जानी है। बता दें कि महाकाल मंदिर में पहले भी एएसआई और जीएसआई की टीम जांच कर चुकी है।

जानकारी के मुताबिक महाकाल मंदिर में समिति सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही आरओ के पानी से ही भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित करते है। हर गाइडलाइन का नियमित रुप से पालन किया जा रहा है। महाकाल मंदिर के प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में जीएसआई की टीम ने किसी तरह की नई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2022 में जीएसआई की टीम ने शिवलिंग की स्थिति का जायजा लिया था। इसमें ये पाया गया था कि वर्ष 2021 में जो सुझाव दिए गए थे उनका पालन नहीं किया गया है, जिससे ज्योतिर्लिंग को नुकसान हो रहा है।

चुनाव आयोग ने जारी की एडवायजरी

दिव्यांगों के लिए अपमान जनक शब्दों का प्रयोग न करें राजनीतिक दल

एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि दिव्यांगजनों के अपमान से जुड़ी भाषा, शब्दावली, संदर्भ, उपहास या किसी भी अपमानजनक संदर्भ का इस्तेमाल करने पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।

निर्वाचन आयोग (ईसी) ने राजनीतिक दलों से भाषणों में दिव्यांगजनों के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। आयोग ने एडवाइजरी जारी कर राजनीतिक दलों ओर उनके उम्मीदवारों से गूंगा, मंदबुद्धि अंधा-काना, बहरा, लंगड़ा, लूला और अपाहिज जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने को कहा हैं। पार्टियों के लिए जारी एक एडवाइजरी में, आयोग ने कहा कि लोकतंत्र की नींव चुनावी प्रक्रिया में सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व में निहित है। आयोग को दिव्यांगों के बारे में राजनीतिक चर्चा के दौरान अपमानजनक या आक्रामक भाषा के उपयोग के बारे में अवगत कराया गया है। राजनीतिक दलों के सदस्यों और उम्मीदवारों की ओर से भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दिव्यांगों के लिए अपमान के तौर पर लिया जा सकता है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को दिव्यांगजनों के अपमान से जुड़ी भाषा से बचने के लिए अपनी प्रचार सामग्री की आंतरिक समीक्षा करनी होगी। एडवाइजरी के मुताबिक, अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल से बचना जरूरी है। राजनीतिक विमर्श में दिव्यांगों को न्याय और सम्मान देना होगा। राजनीतिक दलों को अपने लेखन या राजनीतिक अभियान में किसी भी सार्वजनिक भाषण के दौरान मानवीय अक्षमता के संदर्भ में दिव्यांगता से संबंधित शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए।

एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि दिव्यांगजनों के अपमान से जुड़ी भाषा, शब्दावली, संदर्भ, उपहास या किसी भी अपमानजनक संदर्भ का इस्तेमाल करने पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार विभिन्न मंचों पर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि दिव्यांगजन वास्तव में हमसे अधिक सक्षम हैं। उनके पास हमसे भी बेहतर क्षमताएं हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ सहानुभूति ही नहीं, हर स्तर पर समानता और पहुंच की जरूरत है। चुनाव आयोग की एडवाइजरी के मुताबिक, सभी राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर घोषित करना होगा कि वे दिव्यांगता, लिंग संवेदनशील भाषा और शिष्टाचार का उपयोग करेंगे। साथ ही अंतर्निहित मानवीय समानता, गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान करेंगे। आयोग ने दलों को सलाह दी है कि राजनीतिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाए।

अब भारतीय कम्पनियां अन्य देशों की कम्पनियों का भी अधिग्रहण कर रही

भारत में दवाइयों का निर्माण करने वाली एक कम्पनी सन फार्मा ने भी इजराईल की टेरो फार्मा नामक एक कम्पनी को अपनी सहायक कम्पनी बना लिया है। इससे भारतीय सन फार्मा कम्पनी का विस्तार इजराईल में भी हुआ है।

हाल ही के समय में कई भारतीय कम्पनियां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का स्वरूप ग्रहण करती नजर आ रही हैं। कुछ भारतीय कम्पनियां अन्य देशों की कम्पनियों में न केवल अपना पूंजी निवेश बढ़ा रही हैं बल्कि कुछ कम्पनियां अन्य देशों की कम्पनियों का अधिग्रहण भी कर रही हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आ रहा है कि भारत कई ऐसे देशों, जो आपस में शायद मित्र देश की भूमिका में नहीं हैं इसके बावजूद भारत दोनों देशों, के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाता नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर एवं सऊदी अरब आदि देश मिडल ईस्ट में भारत के महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार हैं एवं ये देश भारत में भारी राशि का निवेश कर रहे हैं। सऊदी अरब तो भारत में 10,000 करोड़ अमेरिक डॉलर का निवेश करने जा रहा है। परंतु, हाल ही के कुछ वर्षों में मिडल ईस्ट के कुछ देशों के साथ ही, इजराईल के साथ भी भारत के मिलिटरी, राजनैतिक एवं व्यापारिक सम्बंध प्रगाढ़ हुए हैं। न केवल इजराईल की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं बल्कि कई भारतीय कम्पनियां भी इजराईली कम्पनियों में निवेश कर रही हैं एवं कुछ कम्पनियों का अधिग्रहण कर रही हैं। इस प्रकार भारत के अरब देशों के साथ साथ इजराईल के साथ भी प्रगाढ़ व्यापारिक रिश्ते कायम हो गए हैं। कई भारतीय कम्पनियां इजराईल के स्टार्ट अप में भारी मात्रा में निवेश करती दिखाई दे रही हैं।

चूंकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद अब लगभग 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को छूने जा रहा है, अतः भारतीय कम्पनियां अब इस स्थिति में पहुंच गई हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरह अन्य देशों में विभिन्न क्षेत्रों में कम्पनियों का अधिग्रहण कर सकें अथवा इन विदेशी कम्पनियों में अपना पूंजी निवेश बढ़ा सकें। इस दृष्टि से भारत की कुछ बड़ी कम्पनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मुकेश अम्बानी समूह), इनफोसिस, विप्रो, टाटा समूह, अडानी समूह आदि इजराईल की कम्पनियों का अधिग्रहण करने में सफलता हासिल कर रही हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इजराईल में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने वाली एक कम्पनी टावर सेमीकंडक्टर नामक कम्पनी का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है। सेमीकंडक्टर चिप के उपयोग हेतु भारत में बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है, इससे इस उत्पाद के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी। इजराईल की उक्त कम्पनी पूर्व में ही भारी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण कर रही है। पूर्व में अमेरिकी कम्पनी इंटेल ने उक्त कम्पनी को 540 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदने का प्रयास किया था परंतु इंटेल को इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकी थी। परंतु, अब भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कम्पनी को खरीदने का प्रयास कर रही है। टावर सेमीकंडक्टर वर्ष 2009 में केवल 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार करती थी परंतु यह वर्ष 2022 में इस कम्पनी का व्यापार बढ़कर 168 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है। अतः यह कम्पनी अत्यधिक तेज गति से प्रगति कर रही है। भारत में दवाईयों का निर्माण करने वाली एक कम्पनी सन फार्मा ने भी इजराईल की टेरो फार्मा नामक एक कम्पनी को अपनी सहायक कम्पनी बना लिया है। इससे भारतीय सन फार्मा कम्पनी का विस्तार इजराईल में भी हुआ है। सन फार्मा को नई तकनीकी को विकसित करने में भी सहायता मिली है। इसी प्रकार, भारतीय कम्पनी अदानी पोर्ट्स एंड लाजिस्टिक्स ने इजराईल के सबसे बड़े हाईफा पोर्ट का विस्तार करने का कार्य हाथ में लिया है। इस विस्तार के कार्य पर 115 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च होगी। वर्ष 2021 में इजराईल के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा इसी पोर्ट के माध्यम से हो रहा था। टाटा समूह की टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) नामक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कम्पनी भी इजराईल में अपने व्यापार का लगातार विस्तार कर रही है। भारत की इनफोसिस कम्पनी ने इजराईल की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की पनाया नामक कम्पनी का 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है।

भारत का टाटा समूह इजराईल के एयर स्पेस में कार्य कर रही कम्पनियों एवं सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही कम्पनियों में अपना निवेश बढ़ा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में इजराईल की कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य किया जा सके। इजराईल के पास सुरक्षा उपकरण बनाने की नवीनतम तकनीक उपलब्ध है। भारत एवं इजराईल अब टैंक्स एवं राडार के निर्माण का कार्य साथ मिलकर करने जा रहे हैं। वैसे भी भारत एवं इजराईल के बीच मिलिटरी सैन्य समझौता पूर्व में ही किया जा चुका है।

कांग्रेस की मध्यप्रदेश विधानसभा में नेहरू की तस्वीर लगाने की मांग

विधानसभा अध्यक्ष समिति गठित करेंगे

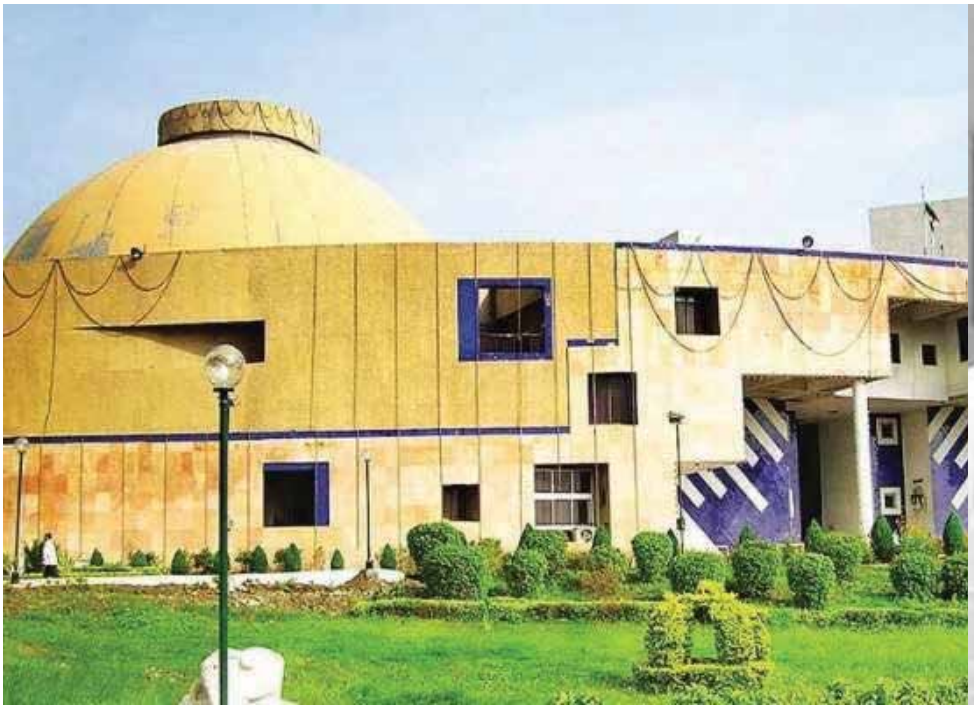

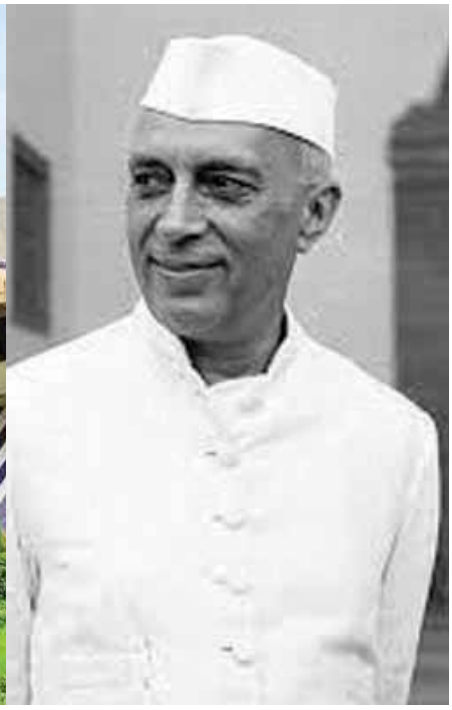

कांग्रेस ने कहा था कि वह सदन में संविधान निर्माता की तस्वीर प्रदर्शित करने का स्वागत करती है, लेकिन इसे महात्मा गांधी और नेहरू की तस्वीरों के साथ रखा जा सकता था। मप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव ए.पी. सिंह ने मंगलवार को कहा था कि पिछले सत्र के दौरान ही नेहरू की तस्वीर की जगह आंबेडकर की तस्वीर लगाई गई थी। उन्होंने कहा, ''तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जुलाई के पिछले सत्र में (नेहरू की) तस्वीर बदलने का निर्देश दिया था क्योंकि यह बहुत पुरानी थी और खराब हो रही थी।'' उन्होंने कहा था, ''तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जुलाई के पिछले सत्र में (नेहरू की) तस्वीर बदलने का निर्देशदिया था क्योंकि यह बहुत पुरानी थी और खराब हो रही थी।''

मध्यप्रदेश विधानसभा से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर हुए विवाद के बीच, नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि सदन में महान नेताओं की तस्वीरें लगाने के बारे में निर्णय लेने के लिए विधायकों की एक समिति गठित की जाएगी। कांग्रेस नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साध रही है। विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे नेहरू की तस्वीर लगी थी और जुलाई में इस तस्वीर को हटाकर संविधान निर्माता डॉ.बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई थी। बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और कांग्रेस के अन्य विधायकों ने यह मुद्दा तब उठाया, जब राज्यपाल मंगूभाई पटेल अभिभाषण दे रहे थे।

सोलहवीं मध्यप्रदेश विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। सिंघार ने मांग की कि सदन में नेहरू की तस्वीर फिर से लगाई जाये क्योंकि वह देश के एक कद्दावर नेता थे और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीर भी विधानसभा में लगाई जानी चाहिए। भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि अध्यक्ष सदन के अंदर नेताओं की तस्वीरें लगाने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए विधायकों की एक समिति गठित करें और उसकी सिफारिशों के आधार पर ऐसे मुद्दों का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, ''विधायी परंपराओं के अनुसार, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है और कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है।

विपक्ष इस मामले को कल फिर से सदन में उठा सकता है।'' कांग्रेस द्वारा उठाई गई मांगों के बीच विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि महान नेताओं की तस्वीरें लगाने के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए विधायकों की एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर ऐसे निर्णय लिये जायेंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि सदन में पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर फिर से लगाई जाये। विधानसभा भवन में प्रवेश करने से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानमंडल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर ''राष्ट्र निर्माता'' का अपमान करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा था कि वह सदन में संविधान निर्माता की तस्वीर प्रदर्शित करने का स्वागत करती है, लेकिन इसे महात्मा गांधी और नेहरू की तस्वीरों के साथ रखा जा सकता था। मप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव ए.पी. सिंह ने मंगलवार को कहा था कि पिछले सत्र के दौरान ही नेहरू की तस्वीर की जगह आंबेडकर की तस्वीर लगाई गई थी। उन्होंने कहा, ''तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जुलाई के पिछले सत्र में (नेहरू की) तस्वीर बदलने का निर्देशदिया था क्योंकि यह बहुत पुरानी थी और खराब हो रही थी।'' उन्होंने कहा था, ''तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जुलाई के पिछले सत्र में (नेहरू की) तस्वीर बदलने का निर्देश दिया था क्योंकि यह बहुत पुरानी थी और खराब हो रही थी। सिंह ने कहा था, ''चूंकि, उस समय आंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, विधानसभा अध्यक्ष ने नेहरू के स्थान पर उनकी तस्वीर लगाने का निर्देश दिया और यह भी सुनिश्चित किया कि नेहरू की तस्वीर पुस्तकालय के गांधी-नेहरू खंड में सम्मानजनक तरीके से रखी जाए।

निगरानी से बचने के लिए तस्कर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे है : बीएसएफ

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि एजेंसी ने भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील बिंदुओं की मैपिंग के अलावा ड्रोन की आवाजाही और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की जांच करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि एजेंसी ने भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील बिंदुओं की मैपिंग के अलावा ड्रोन की आवाजाही और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की जांच करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। बीएसएफ के पश्चिमी कमान के विशेष महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया ने चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीएसएफ भारत-पाक सीमा पर ड्रोनों की आवाजाही पर नजर रख रही है और पिछले साल के दौरान 95 से अधिक ड्रोनों को मार गिराया है।

खुरानिया ने कहा, 'कुल 95 में से अधिकांश ड्रोन सीमा के पंजाब की ओर मार गिराए गए, जबकि कुछ को राजस्थान के गंगनार इलाके में मार गिराया गया।' उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने ड्रोन खतरे से निपटने के लिए एक एसओपी तैयार की है। बीएसएफ के विशेष डीजीपी ने कहा कि असामाजिक तत्व नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान पंजाब और जम्मू-कश्मीर के तस्करों के बीच अंतर-जिला और अंतर-राज्य संबंध भी स्थापित हुए हैं।

खुरानिया ने कहा, 'हमने ड्रोन की आवाजाही की जांच करने के लिए एक एसओपी विकसित किया है। बीएसएफ जवानों को प्रशिक्षित किया गया है और वे ड्रोन तकनीक से अच्छी तरह परिचित हैं।' उन्होंने कहा कि बढ़ती निगरानी के कारण तस्करों ने बड़े ड्रोन का इस्तेमाल बंद कर दिया है। योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा कि तस्कर पहले भारी लिफ्ट ड्रोन का उपयोग कर रहे थे जो तीन से पांच किलोग्राम के बीच पेलोड ले जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब वे 400 से 500 ग्राम पेलोड क्षमता वाले छोटे ड्रोन का उपयोग कर रहे थे, जिनकी कीमत मामूली थी। योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा, 'छोटे ड्रोन को पहचानना मुश्किल हो सकता है लेकिन बीएसएफ किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है।' बीएसएफ के स्पेशल डीजी ने पंजाब पुलिस के नियम की सराहना करते हुए कहा कि यह पुलिस की मदद के कारण ही था कि बीएसएफ सीमा पर संवेदनशील बिंदुओं का पता लगाने में सक्षम थी।

उन्होंने कहा कि ग्रे क्षेत्रों को सूचीबद्ध करने के बाद, सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है और परियोजना मार्च 2024 के अंत तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बाड़ लगाने के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है और इसे लागू किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद। खुरानिया ने कहा, 'हमने पहले से ही इन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और किसी भी गतिविधि की जांच के लिए प्रौद्योगिकी की मदद ले रहे हैं।'

बीएसएफ डीजी ने एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में आने के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर अवैध खनन बंद हो गया है।

50 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा पोत

फरवरी में भारतीय नौसेना बनेगी सबसे बड़े युद्धाभ्यास की मेजबान

मिलन भारत की नौसेना की तरफ से किय जाने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। आखिरी बार 2022 में हुए इस युद्धाभ्यास में 46 मित्र देशों को न्योता भेजा गया था। इनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य शामिल रहे थे। भारतीय नौसेना फरवरी 2024 में अपने सबसे बड़े नौसैनिक युद्धाभ्यास- मिलन 2024 का आयोजन करने जा रही है। 19 से 27 फरवरी के बीच विशाखापत्तनम में चलने वाले इस अभ्यास में इस बार 50 से ज्यादा मित्र देशों के शामिल होने की संभावना है। वहीं, 20 से ज्यादा नौसैनिक पोत भी इस अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। भारतीय नौसेना ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। गौरतलब है कि मिलन भारत की नौसेना की तरफ से किय जाने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। आखिरी बार 2022 में हुए इस युद्धाभ्यास में 46 मित्र देशों को न्योता भेजा गया था। इनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य शामिल रहे थे।

क्या है मिलन अभ्यास? : यह सबसे जटिल नौसैनिक अभ्यास है जो भारत किसी भी अन्य देश के साथ करता है। मिलन एक बहुपक्षीय युद्ध नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1995 में शुरू किया गया था। उद्घाटन संस्करण में भारतीय नौसेना के अलावा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया था।

इस आयोजन का भारत के लिए क्या महत्व है? : विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आयोजन उपमहाद्वीप के समुद्र तटों में भारत की समुद्री श्रेष्ठता को दिखाने और उसकी समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के मद्देनजर चीन की घेराबंदी के लिए यह जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन का नौसैनिक विस्तार भारत के लिए चुनौतियां पैदा करता है इसलिए भारत के लिए ऐसे अभ्यासों की बहुत जरूरत है। हिंद महसागर तेजी से चीन और भारत के लिए एक भू-रणनीतिक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, क्योंकि दोनों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक तरफ जहां चीन आर्थिक और रणनीतिक लाभ हासिल करने के लिए रणनीतिक बंदरगाहों तक पहुंच सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है, वहीं भारत की भूमिका को समुद्री मार्ग और नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षक के रूप में देखा जा रहा है। इस अभ्यास के जरिए भारत को अलग-अलग देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और समुद्री सहयोग हासिल करने का एक मौका मिलता है।

नए भारत का नया कानून : पीएम मोदी मिटा रहे गुलामी के निशान

मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, प्रॉपर्टी जब्त... नए कानून में कितनी सजा

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त में पांच प्रण दिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि गुलामी की जितनी भी निशानियां हैं उससे मुक्ति पाना सबसे पहले काम है। गुलामी की सबसे बड़ी निशानी होने का ठप्पा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंश एक्ट पर था। 1830, 1856, 1872 उस दौरान इन सब चीजों को लाया गया और हम अब तक ढो रहे थे। आईपीसी का असल में नाम आयरिश पीनल कोड था। ये बात तो सभी जानते हैं कि अंग्रेज हिन्दुस्तान की जनता को सहूलियत देने के लिए कानून नहीं बनाते थे। किस तरह से हम सभी को सिस्टम के प्रति एक गुलाम की तरह ट्रीट करे। संविधान तो तैयार कर लिया गया लेकिन अपराध और अपराधियों को पकड़ने का सिस्टम अंग्रेज के जमाने से था। एक शख्स था थोमस बैबिंगटन मैकाले ये भारत तो आया था अंग्रेजी की पढ़ाई करने लेकिन उसके बाद इसी भारत में अगर किसी ने देशद्रोह का कानून ड्राफ्ट किया तो वो लार्ड मैकाले ही था। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने ऐसा काम किया है। गुलामी की जंजीरों से पूरे सिस्टम को आजादी दी है।

मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड : शाह ने संसद को यह भी बताया कि केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान लागू है। जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। नए प्रावधान में कहा गया है कि आजीवन कारावास या सात साल से कम की कैद नहीं होगी और जुर्माना भी देना होगा।

धर्म छुपाकर शादी करने वाला जेल की हवा खाएगा

इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने के अलावा रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे के तहत महिलाओं के साथ पहली बार संबंध बनाना अपराध होगा। यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा।

तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल पर क्या बोले अमित शाह

लोकसभा ने बुधवार को तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित किए, जिनका उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। विधेयक में भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता को बदलने का प्रस्ताव करती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता को बदलने का प्रयास करती है और भारतीय साक्ष्य संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेती है। लोकसभा में विधेयकों को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा आपराधिक कानून न्याय प्रदान करने के बजाय दंडित करने के इरादे से औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं। अमित शाह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य दंड देना था, न्याय नहीं; इसके स्थान पर भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 सदन से पारित होने के बाद देश में लागू होगी। गृह मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानून विधेयक संविधान की भावना के अनुरूप हैं।

अब राज्यसभा की बारी : विधेयकों को शुरू में संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन बाद में वापस ले लिया गया। अमित शाह ने पिछले हफ्ते लोकसभा में संशोधित बिल दोबारा पेश किया। लोकसभा से पास होने के बाद अब बिल को राज्यसभा में 21 नवंबर को पेश किया जाएगा।

बृज भूषण के वफादार संजय सिंह के WFI के अध्यक्ष चुने जाने से नाराज हैं रेसलर

साक्षी मलिक ने कुश्ती से रोते हुए लिया संन्यास..

रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने प्रेस को एक भावनात्मक संबोधन में बृज भूषण शरण सिंह के वफादार संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह कुश्ती छोड़ने जा रही हैं।

रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने प्रेस को एक भावनात्मक संबोधन में बृज भूषण शरण सिंह के वफादार संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह कुश्ती छोड़ने जा रही हैं। गुरुवार, 21 दिसंबर को नई दिल्ली में हुए बहुप्रतीक्षित डब्ल्यूएफआई चुनावों में संजय सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण को 7 के मुकाबले 40 वोटों से हराया। साक्षी मलिक ने राजधानी में प्रेस से बात करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के परिवार और करीबी सहयोगियों को अनुमति न देने के खेल मंत्रालय ने पहलवानों से किए वादे पूरे नहीं किए। साक्षी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, बृजभूषण शरण सिंह के दाहिने हाथ थे।

टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया के साथ प्रेस को संबोधित करने वाली साक्षी मलिक अपने आंसुओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर रो पड़ीं। साक्षी ने बृज भूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के पिछले शासन के खिलाफ अपने बहुचर्चित विरोध के दौरान समर्थन के लिए जनता और मीडिया को धन्यवाद दिया।

स्टार ने कहा, 'हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। पहलवान ने गुरुवार को कहा अगर बृज भूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी को डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष चुना जाता है, तो मैं कुश्ती छोड़ दूंगा।' राजधानी में भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साक्षी को रोते हुए परिसर से बाहर निकलते देखा गया। बृज भूषण शरण सिंह से साक्षी मलिक की टिप्पणी के बारे में पूछा गया, लेकिन पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। सिंह ने गुरुवार को कहा, 'इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।'

'हमने एक महिला की मांग की'

साक्षी और अन्य पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए अनीता श्योराण का समर्थन किया। अनीता राष्ट्रीय कुश्ती संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनने के लिए बोली लगा रही थीं, लेकिन वह चुनाव हार गईं और 47 में से केवल 7 वोट हासिल कर पाईं। साक्षी ने कहा, 'हमने महिला अध्यक्ष की मांग की है। अगर अध्यक्ष महिला होगी तो उत्पीड़न नहीं होगा। लेकिन, पहले महिलाओं की भागीदारी नहीं थी और आज आप सूची देख सकते हैं, एक भी महिला को पद नहीं दिया गया।' साक्षी ने कहा, 'हम पूरी ताकत से लड़े थे लेकिन यह लड़ाई जारी रहेगी। नई पीढ़ी के पहलवानों को लड़ना होगा।'

ब्रिज भूषण का विरोध क्यों?

विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित शीर्ष ओलंपियन एक नाबालिग सहित सात पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अपने महीनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर होने के बाद, जून में पांच महीने से अधिक समय के बाद उन्होंने अपना विरोध बंद कर दिया। डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ शिकायतों में अनुचित तरीके से छूने, लड़कियों की छाती पर हाथ रखने, छाती से पीठ की ओर हाथ ले जाने और उनका पीछा करने जैसे अन्य प्रयासों का जिक्र किया गया है।

छत्तीसगढ़ में पांचवीं पास मजदूर ने छह बार के विधायक को हराया...

मध्यप्रदेश-राजस्थान में भी ये दिग्गज हारे

चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के कई नतीजों ने सभी को चौंकाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पांच या इससे अधिकर बार के विधायक भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इनमें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी बहुत चर्चित नाम है।

चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बाजी मारी तो तेलंगाना में कांग्रेस को सफलता मिली। इन चुनाव नतीजों में कई ऐसे भी थे, जिसने सभी को चौंकाया। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कई नेता ऐसे थे, जो पांच या इससे अधिकर बार के विधायक थे, लेकिन इस बार अपनी सीट ही गंवा बैठे। रविवार को चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बाजी मारी तो तेलंगाना में कांग्रेस को सफलता मिली। इन चुनाव नतीजों में कई ऐसे भी थे, जिसने सभी को चौंकाया। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कई नेता ऐसे थे, जो पांच या इससे अधिकर बार के विधायक थे, लेकिन इस बार अपनी सीट ही गंवा बैठे।

आइये जानते हैं दिग्गज जो सीट हारे और उन्हें हराने वाले को...

शिवपुरी में केपी सिंहः छह बार के विधायक केपी सिंह नहीं बचा पाए अपनी सीट... मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे केपी सिंह शिवपुरी सीट पर अपना चुनाव हार गए। केपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी के देवेन्द्र कुमार जैन के हाथों 43,030 वोटों के बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी। यहां मौजूदा विधायक यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने का एलान के बाद जैन को भाजपा ने टिकट दिया था, जो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे। दरअसल, केपी सिंह शिवपुरी जिले की ही पिछोर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह इस सीट से लगातार छह चुनाव जीते। उन्होंने 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में पिछोर सीट पर कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की है। इस बार पार्टी ने उन्हें पिछोर की जगह शिवपुरी से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन बाजी किसी और ने मार ली।

कृषि मंत्री कमल पटेल : कृषि मंत्री कमल पटेल रोचक मुकाबले में हारे... प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी हार गए। वे हरदा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के रामकिशोर डोगने से उनका मुकाबला था। कई राउंड में आगे-पीछे होते रहे। आखिरी में 870 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कमल पटेल ने 1993, 1998, 2003, 2008 और 2018 में हरदा सीट से पांच बार विधानसभा का चुनाव जीता। अप्रैल 2020 में उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और वर्तमान में वे मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

गौरीशंकर बिसेन : पांच बार के विधायक बिसेन को झटका... बालाघाट सीट से शिवराज सरकार में मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी अपना चुनाव हार गए। पांच बार के विधायक को कांग्रेस की अनुभा मुंजारे ने 29,195 वोटों से हराया। 1985 में बिसेन बालाघाट विधानक्षेत्र सीट पर विजयी हुए थे। वह मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पांच बार चुने गए। 1998 और 2004 में वह बालाघाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी बने। बिसेन 2008 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे।

पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह : सात बार के विधायक नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह भी हारे... भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट के नतीजों ने भी सभी को चौंकाया। लहार से मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह चुनाव मैदान में थे। भाजपा की ओर से मैदान में उतरे अंबरीश शर्मा गुड्डू ने दिग्गज कांग्रेस नेता को 12,397 वोटों के अंतर से हरा दिया। डॉ. गोविंद सिंह 1990 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे। इसके बाद वह 1993, 1998, 2003, 2008 2013 और 2018 में विधानसभा चुनाव में भी विजयी हुए। 2018 में बनी कमलनाथ वाली कांग्रेस सरकार में गोविंद सिंह मंत्री भी बनाए गए थे।

रविंद्र चौबे : छत्तीसगढ़ में गैर-राजनीतिक व्यक्ति ने कद्दावर मंत्री को शिकस्त दी... छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी कई उलटफेर देखने को मिले, जिसमें वरिष्ठ नेता रवींद्र चौबे की हार भी शामिल है। बेमेतरा जिले की साजा सीट से कांग्रेस के मंत्री रविंद्र चौबे को भाजपा की तरफ से उतरे ईश्वर साहू ने हराकर सबको चौंका दिया। छह बार के विधायक रहे रवींद्र को 5,196 वोटों के अंतर से हार झेलनी पड़ी। ईश्वर साहू ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि वह पांचवीं पास हैं और मजदूरी का काम करते हैं और पत्नी गृहिणी हैं। उनके बेटे भुवनेश्वर साहू की बिरनपुर गांव में

भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। चुनाव में भाजपा ने ईश्वर को टिकट थमा दिया और वोट के बदले अपने बेटे के लिए इंसाफ देने की बात कहने वाले भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए। रवींद्र चौबे कांग्रेस के पुराने और कद्दावर नेता हैं। 1985 में अविभाजित मध्य प्रदेश में चौबे पहली बार विधायक बने और ये सिलसिला 1990, 1993 और 1998 के विधानसभा चुनावों में भी जारी रहा। वहीं छत्तीसगढ़ बनने के बाद चौबे 2003 और 2008 के राज्य विधानसभा के चुनावों में भी जीते। अविभाजित मध्यप्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ में कई विभागों के मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुके चौबे 28 सालों तक विधायक रहे। 2013 के चुनावों में पहली बार कांग्रेस नेता के हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अगले ही चुनाव में 2018 में उन्होंने फिर से जीत हासिल की थी।

डॉ सी पी जोशी : राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हारे... राजस्थान में भी कई दिग्गजों का दांव परास्त हो गया। विधानसभा चुनावों में नाथद्वारा सबसे हॉट सीटों में से एक थी। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी का मुकाबला भाजपा के उदयपुर राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ से था, जिसे उन्होंने 7,504 वोटों से जीत लिया। सीपी जोशी इस सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं। उनकी सीट नाथद्वारा काफी चर्चा में रहती है, क्योंकि 2008 में यहां एक वोट से सीपी जोशी को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के कल्याण सिंह ने 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी को एक वोट से हराया था। कल्याण सिंह को 62,216 वोट मिले थे और सीपी जोशी ने 62,215 वोट हासिल किए थे।

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ : नेता प्रतिपक्ष और सात बार के विधायक राजेंद्र राठौड़ हारे... चूरू जिले की तारानगर विधानसभा सीट पर सात बार के विधायक राजेंद्र राठौड़ को हार झेलनी पड़ी। 68 साल के राठौड़ को कांग्रेस के नरेन्द्र बुडानिया ने 10,345 वोटों से हराया। इसी साल अप्रैल में नेता प्रतिपक्ष बनने वाले राजेंद्र 1990 में पहली बार विधायक बने थे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ 1990 से 2018 तक लगातार चूरू विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करते रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राठौड़ को चूरू की ही तारानगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। इसके पहले 2008 में भी वे इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। इस बार सीट में हुए बदलाव का फैसला राजेंद्र सिंह राठौड़ अपने पक्ष में नहीं कर पाए और चुनाव हार गए।

मध्यप्रदेश में नवनिर्वाचित 90 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले, 205 करोड़पति

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 90 में से 34 के खिलाफ गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में केस दर्ज हैं। 90 दागी विधायकों में से 51 भाजपा के हैं, 38 कांग्रेस और एक भारतीय आदिवासी पार्टी से है। वर्ष 2018 की तुलना में इस बार दागियों की संख्या थोड़ी कम हुई है। 2018 में 94 दागी विधायक चुने गए थे।

मध्य प्रदेश में जीतने वाले 230 विधायकों में से 90 यानी 39 फीसदी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक 90 में से 34 के खिलाफ गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में केस दर्ज हैं। 90 दागी विधायकों में से 51 भाजपा के हैं, 38 कांग्रेस और एक भारतीय आदिवासी पार्टी से है। वर्ष 2018 की तुलना में इस बार दागियों की संख्या थोड़ी कम हुई है। 2018 में 94 दागी विधायक चुने गए थे।

राज्य में 12 फीसदी महिला विधायक : दिलचस्प बात यह है कि लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं के वोट से चुनाव में भाजपा को बंपर जीत मिली और कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं के वादे किए। लेकिन, 230 में से केवल 27 यानी 12 फीसदी विधायक ही महिला चुनी गई हैं। इस बार चुने गए 230 में से 205 यानी 89 फीसदी विधायक करोड़पति हैं। इनमें से 144 भाजपा से और 61 कांग्रेस से जुड़े हैं। 2018 में 187 विधायक करोड़पति थे। रतलाम से भाजपा के विधायक चेतन्य कश्यप सबसे अमीर विधायक हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 296 करोड़ रुपये है। इसी तरह विजयराघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक 242 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, कांग्रेस में कमलनाथ 134 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर विधायक हैं।

छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित विधायकों में 17 दागी : इधर, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीतने वाले 90 विधायकों में से 17 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें छह के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 24 यानी 27 फीसदी विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। इस तरह पिछले बार की तुलना में इस बार दागी विधायकों की संख्या में कमी आई है। इन 17 विधायकों में से 12 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि 5 कांग्रेस के हैं। इसी तरह से गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने वालों में भाजपा के चार और कांग्रेस के 2 विधायक शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव और अटल श्रीवास्तव कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं।

72 विधायक करोड़पति

छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित 90 में से 72 विधायक करोड़पति हैं। पिछली विधानसभा की तुलना में इस सूची में चार विधायक अधिक हैं। राज्य में करोड़पति विधायकों में भाजपा शीर्ष पर हैं। हाल ही में हुए चुनावों में भारी जीत हासिल करने वाली भाजपा के 43 विधायक करोड़पति हैं। कांग्रेस 29 करोड़पति विधायकों के साथ दूसरे स्थान पर है। हाल ही में हुए चुनाव में 90 सीटों में से भाजपा ने 54 और कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत हासिल की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच की ओर से किए गए विश्लेषण के अनुसार, भाजपा के 80 प्रतिशत और कांग्रेस के 83 फीसदी विधायक करोड़पति हैं। इस बार के राज्य विधानसभा चुनावों में जीतने वाले प्रति उम्मीदवार की औसत संपत्ति 5.25 करोड़ रुपये है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनावों में यह 11.63 करोड़ रुपये थी। 33.86 करोड़ की संपत्ति के साथ भाजपा के पहली बार चुने गए विधायक भवन बोहरा (पंडरिया सीट) करोड़पति विधायकों में शीर्ष पर हैं, इसके बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल (पाटन निर्वाचन क्षेत्र) 33.38 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

जनता ने सिर्फ सरकार नहीं बदली कांग्रेस को सबक भी सिखाया...

राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य को सही मायने में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ भी नया नहीं है... तीन दशक से राजस्थान में हर पांच साल में सरकार को घर बिठाने की परंपरा रही है... एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी...

राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनको अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कह दिया है। गहलोत के इस्तीफे का कारण यही है कि राजस्थान में राज बदल गया मगर रिवाज नहीं बदला। राज बदलते ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा वाजिब था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि न तो राजस्थान में राज बदलेगा और रिवाज भी नहीं बदलेगा। उनका मतलब था कि कांग्रेस की सरकार फिर आएगी और हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज है वह इस बार बदल जाएगा। मगर, ऐसा नहीं हो सका। राजनीति में वैसे भी नेता के मन का होता कहां है, होता तो आखिर वही है जो जनता चाहती है। जनता ने चाहा और राज बदल गया। कांग्रेस चली गई, और गहलोत भी जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेते ही वे भी भूतपूर्व हो जाएंगे।

राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य को सही मायने में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ भी नया नहीं है। तीन दशक से राजस्थान में हर पांच साल में सरकार को घर बिठाने की परंपरा रही है। एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी। बारी-बारी से दोनों पार्टियों को लोग सरकार में लाते रहे हैं। हालांकि, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में गहलोत ने समाज के हर वर्ग के लिए सरकार के खजाने खोल कर कुछ अलग तरह की जादूगरी दिखाने के सारे प्रयास किए, लेकिन उनके मंत्रियों व विधायकों के भ्रष्टाचार के कारण उनका जादू हर स्तर पर लगातार फेल होता ही नजर आया। हालांकि, गहलोत हर संभव कोशिश करते रहे। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देकर एक बड़े वर्ग को साधने के लिए सरकार के दांव को परफेक्ट समझना कहीं न कहीं बड़ी गलती रही, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने ही उनको वोट नहीं दिया। फिर महिला सशक्तिकरण के नाम पर योजनाओं और धन लक्ष्मी जैसी योजनाओं का भी असर ग्राउंड स्तर पर ज्यादा लाभकारी साबित नहीं हो सका, क्योंकि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं थे। सही मायने में देखें, तो जनता को जो सबसे बड़ा लाभार्थी तबका, जिसको लेकर कांग्रेस आश्वस्त थी कि वह उसी को वोट देगा, वही साथ छोड़कर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया और कांग्रेस उसे समझ भी नहीं सकी।

राजस्थान में कांग्रेस के 30 विधायक कम पड़ गए हैं। पिछली विधानसभा में 99 थे मगर अब 69 ही जीते हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस सरकार के 17 मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री के 5 सलाहकार भी चुनाव हार गए हैं। ये सभी 17 मंत्री, गोविन्द राम मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, रमेश मीणा, परसादी लाल मीणा, विश्वेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, शकुंतला रावत, राजेंद्र यादव, बीडी कल्ला, सालेह मोहम्मद, राम लाल जाट, सुखराम विश्नोई, उदयलाल आंजना, जाहिदा खान, प्रमोद जैन भाया और भजन लाल जाटव राजस्थान सरकार में काफी महत्वपूर्ण विभाग के मुखिया थे तथा गहलोत सरकार के ताकतवर नेता थे। मगर प्रदेश की जनता ने उन्हें हरा दिया। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मंत्री रघु शर्मा भी चुनाव हार गए। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार अपने विकास व जनसेवा

के कार्यों को जबरदस्त अभियान के तहत जनता तक ले गई, उसी सरकार के 17 मंत्री, 5 सलाहकार व दस बड़े नेता चुनाव हार गए।

देखा जाए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस बार के 5 साल के कार्यकाल में सबसे पहले तो अपने साथी सचिन पायलट से जूझते रहे, फिर लगभग डेढ़ साल तक कोरोना से जूझे, एक के बाद एक घोषणाओं और योजनाओं के दौर चले। जमता को अपनी योजनाओं से लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हुए वे अपनी सरकार बचाने के भी हर कोशिश करते रहे। इसे इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि गहलोत ने एक तरह से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसके लिए उन्होंने सरकारी खजाने के खाली होने की भी परवाह नहीं की। खासकर एक के बाद एक योजनाओं के जरिए महिला सशक्तिकरण और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। मगर कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उससे चूक कहां हो गई, जो राजस्थान की जनता उसके बजाय बीजेपी को बहुमत देकर उसके साथ खडी हो गई।

राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ने के कारण तलाशे जा रहे हैं। क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह पार्टी के लिए बुरी हार का कारण बनी, या पार्टी का लचर संगठन हारने के लिए जिम्मेदार रहा, या फिर राज्य की जनता को नए नेतृत्व की चाह थी। क्या बाबा बालकनाथ के नाम पर यूपी की तरह राजस्थान में भी योगी फैक्टर चला या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अटूट विश्वास था और या फिर वसुंधरा राजे पर एक बार फिर लोगों ने विश्वास जताया। कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि उसको सत्ता से बेदखल क्यों होना पड़ा। इन सारे ही सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों इतना सब करने के बाद भी कांग्रेस की हालत इतनी खराब हुई। दरअसल कांग्रेस की अंतर्कलह से प्रदेश की जनता खुद ही परेशानी में थी। लगातार 5 साल तक सचिन पायलट के सीएम बनने के सपने ने कांग्रेस को जिस कलह तक पहुंचाया, और गहलोत के कुर्सी बचाने के द्वंद्व को इतना ताकतवर बना दिया कि गहलोत जैसा सहज, सरल व सदाशयी नेता भी जनता को पदलोलुप नजर आने लगा। इस चुनाव से पहले गहलोत की छवि ऐसी कभी नहीं रही। फिर, सबसे बड़ा कारण रहा उनके मंत्रियों व विधायकों के भारी भ्रष्टाचार का, बीजेपी ने हर स्तर पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुंचाया व यह सुनिश्चित किया कि लोग उस हर बात को समझें कि कांग्रेस के भ्रष्ट विधायक जनता को किस तरह से लूट रहे हैं। उधर, सरकार भी जनता के काम व परेशानियों को भूल कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को सुलझाने में वक्त जाया करती रही, इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ।

कांग्रेस की हार का एक जो सबसे बड़ा कारण रहा, वह यह भी कहा जा सकता है कि राजस्थान के चुनाव में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कोई उत्साह नहीं दिखा। राहुल गांधी तो बोलते बोलते अपनी ही पार्टी की सरकार के जाने तक की बात बोल गए थे। हालांकि राहुल के कहने से राजस्थान में वोट नहीं पड़ते, पर वे भी निराशा में प्रचार करने ऐन मौके पर ही पहुंचे। कांग्रेस का प्रचार अभियान जनता में जोर पकड़ ही नहीं सका, क्योंकि उसके सारे बड़े नेता अपनी सीट बचाने में ही उलझे रहे। मगर, चुनाव से कुछ समय पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने भी बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त हवा बनाई। जबकि कांग्रेस एक कदम पीछे दिखी और पार्टी के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी लोगों को हर स्तर पर परेशान करती रही और लगने लगा कि कांग्रेस हार रही है, जोकि सही साबित हुआ और राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। मगर, सवाल यह है कि इस हार से कांग्रेस कोई सबक लेगी?

विष्णुदेव साय बने छग के नए मुख्यमंत्री...

विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला

छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का एलान हो गया है। विष्णुदेव साय को अब राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री है। ये फैसला विधायक दल की बैठक में किया गया। विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है।

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को अब राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। ये फैसला विधायक दल की बैठक में लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है।

भाजपा के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम की रायपुर में नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक में ये फैसला किया गया है। रायपुर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में सभी ने मिलकर विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने पर मुहर लगाई है। बता दें कि विष्णु देव साय मूल रूप से आदिवासी समाज के बड़े नेता है। आदिवासी समाज राज्य का बड़ा समुदाय है।

विष्णुदेव साय राज्य में एक बड़ा चेहरा है, जो चार बार सांसद, दो बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और दो-दो बार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके है। साय के बाद संगठन में काम करने के संबंध में काफी लंबा अनुभव भी है। बता दें कि विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर उपस्थित थे। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर घंटों तक मंथन चला था। विधायक दल में नाम तय होने के बाद दिल्ली को भी जानकारी भेजकर मुहर लगवाई गई।

छत्तीसगढ़ में तीन दिसंबर को विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। बता दें कि इस बार भाजपा ने किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की थी और पार्टी बिना मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किए ही मैदान में उतरी थी। चुनाव जीतने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कई अटकलें आ रही थी, जिनपर अब विराम लग गया है।

2024 की राह आसान नहीं, जीत के बाद भी सामने हैं कई बड़ी चुनौतियां

जाहिर सी बात है कि इन नतीजों ने 2024 से पहले भाजपा के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भाजपा के लिए 2024 की राह थोड़ी आसान हुई है। हालांकि भाजपा के लिए आने वाले तीन से चार महीने काफी चुनौती पूर्ण रह सकते हैं। भाजपा ने हिंदी पट्टी के तीन राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। भाजपा ने जहां मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को बरकरार रखा है तो वहीं कांग्रेस को उसने छत्तीसगढ़ और राजस्थान से बेदखल किया है। 2024 के लिहाज से यह भाजपा की यह बड़ी जीत हैं। इस जीत का श्रेय पूरी तरीके से पीएम मोदी को दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि ब्रांड मोदी 2024 से पहले एक बार फिर से मजबूत हुआ है। हालांकि, इन तीनों ही राज्यों में बड़ी जीत के बावजूद भी भाजपा के लिए चुनौतियां अभी भी बरकरार है।

जाहिर सी बात है कि इन नतीजों ने 2024 से पहले भाजपा के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भाजपा के लिए 2024 की राह थोड़ी आसान हुई है। हालांकि भाजपा के लिए आने वाले तीन से चार महीने काफी चुनौती पूर्ण रह सकते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री को लेकर जो फैसला किया जाना है उसमें ऐसे नाम को आगे बढ़ाया जाए जो सभी को स्वीकार हो। इसके अलावा जो भी वादे किए गए हैं उसे जमीन पर उतारने की शुरूआत की जा सके। साथ ही साथ पार्टी के भीतर जिस तरह की एकता इन विधानसभा चुनावों के दौरान दिखी है वह लगातार बरकरार रहे।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखें तो सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। नतीजे आए दो दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा में टेंशन बढ़ती जा रही है। वसुंधरा राजे जहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में हैं तो वही मुख्यमंत्री पद की रेस में गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालक नाथ, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी जैसे नाम भी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का भी नाम चर्चा में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहां सीएम शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य में पार्टी का पिछले 18 वर्षों से नेतृत्व किया है। ऐसे में उन्हें किनारे करना पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद सिंह पटेल भी मुख्यमंत्री पद की रेस है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री का रेस दिलचस्प है। यहां रमन सिंह प्रबल दावेदारों में से जरूर हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह, अरुण साव और ओपी चौधरी जैसे नाम की भी चर्चा तेज है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की ओर से लोक लुभावने वादे किए गए थे जिसे लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराना, गरीब परिवार की बच्चियों की 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त, हर महीने 100 यूनिट तक की बिजली सिर्फ 100 में, लाडली बहन योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, आने वाले समय में से 3000 तक करने का वादा किया गया है। किसान सम्मान के तहत 12000 देने की बात कही गई है। वहीं गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल और चावल की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का भी वादा है।

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन स्कीम के तहत सालाना शादीशुदा महिलाओं को 12000 देने के वादा, किसानों को साल भर में 10000 रुपये देने की बात, 500 रुपये में सिलेंडर, छात्रों को हर महीने ट्रैवल एलाउंस और 2 साल में एक लाख सरकारी पदों को भरने का वादा है।

राजस्थान की बात करें तो यहां 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा है। वहीं 5 साल में ढाई लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के बाद कही गई है। किसान सम्मन निधि के तहत मिलने वाली रकम को 12000 रुपये करने का वादा किया गया है। महिलाओं को लेकर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने और एंटी रोमियो स्क्वायड के गठन करने की बात है। 12वीं की परीक्षा पास करने वाली मेधावी लड़कियों को फ्री स्कूटी देने की भी बात कही गई है। वहीं, गरीब परिवार की लड़कियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है।

हार के बाद भी आखिर क्यों रेस से बाहर नहीं हुए नरोत्तम मिश्रा

चुनाव हारने के बाद डॉ. मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच शायरी करते हुए नजर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा अपनी हार पर कहते हैं, 'इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ऐ बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं।'

आमतौर पर ऐसी कहावत कि प्यार में टूटा प्रेमी और चुनाव में हारा नेता शायर बन जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया मध्यप्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के साथ देखने को मिल रहा है। दतिया सीट से मिली शिकस्त के बाद हर तरफ उनकी हार के चर्चे हो रहे हैं। लेकिन हार के बाद भी उनके बयान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। चुनाव हारने के बाद डॉ. मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच शायरी करते हुए नजर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा अपनी हार पर कहते हैं, 'इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ऐ बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं।' उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा, मैं लौटकर वापस आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा है। इस बीच चर्चाएं यह भी जोर पकड़ने लगी हैं कि डॉ. मिश्रा उप चुनाव लड़ सकते हैं और वो सीट मुरैना जिले की दिमनी भी हो सकती है। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में वे किसी बड़ी जिम्मेदारी पर आ सकते हैं। एक चर्चा यह है कि भविष्य में हाईकमान उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप सकता है। क्योंकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। डॉ. मिश्रा दतिया सीट से चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ थे। लेकिन यहां से कांग्रेस उम्मीदवार भारती राजेंद्र ने 7,742 वोटों से जीत हासिल की है। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने 2008, 2013 और 2018 में जीत हासिल की है।

डॉ. मिश्रा मध्यप्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्रियों में गिने जाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में हार की वजह से उनके राजनीतिक भविष्य पर चर्चाएं होने लगी हैं। दरअसल, भाजपा ने 2018 के चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए तीन केंद्रीय मंत्रियों, चार सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव को टिकट दिया था। इन नामों में सिर्फ सतना से सांसद गणेश सिंह और मंडला की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हारे हैं। बाकी अन्य सीटों पर सभी ने चुनावी जीत हासिल की है। इसमें एक नाम मुरैना जिले की दिमनी सीट का भी है। यहां से पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में तोमर ने बसपा उम्मीदवार बलवीर सिंह दंडोतिया को हराया था। अब नरोत्तम की हार और कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव करीब आने से इस सीट के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा ने दिमनी सीट जीतने का टारगेट तय किया था। पार्टी ने बड़े संघर्ष के साथ हासिल भी कर लिया है। भाजपा अगर नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम बनाती है, तो विधायक पद छोड़ने की बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तोमर के अलावा कोई अन्य

नेता सीएम बनता है, तो फिर तोमर विधायक सीट छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि वे मुरैना लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। केंद्र में कृषि मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। तोमर की गिनती मोदी के करीबी मंत्रियों में होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं। ऐसे में मुरैना जैसी लोकसभा सीट जीतना भी हर किसी नेता के लिए आसान नहीं हैं।

दिमनी विधानसभा में ठाकुर और ब्राह्मणों का वर्चस्व

दिमनी विधानसभा सीट पर ठाकुर और ब्राह्मण वोटर्स ही उम्मीदवारों की हार-जीत तय करते हैं। ठाकुर वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद निर्णायक स्थिति में ब्राह्मण मतदाता आते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने बलवीर सिंह दंडोतिया पर दांव खेला था। वे ब्राह्मण समाज से आते हैं। जबकि कांग्रेस ने तोमर समाज से उम्मीदवार उतारा था। ऐसे में दो तोमर और एक ब्राह्मण उम्मीदवार होने से यह लड़ाई कहीं ना कहीं ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच देखी गई। अंत में नरेंद्र सिंह तोमर ने बाजी मार ली। डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से पहले ग्वालियर जिले की डबरा सीट से भी चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। लेकिन बाद में वो दतिया सीट से चुनाव लड़ने लगे। दतिया और दिमनी के बीच 140 किमी की दूरी है। मिश्रा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अगर भाजपा मिश्रा को दिमनी से टिकट देती है, तो वहां सोशल इंजीनियरिंग दुरुस्त करने में बड़ी मदद मिल सकती है। ठाकुर के साथ-साथ ब्राह्मण समाज को भी अपने पाले में किया जा सकता है। इसके लिए नरोत्तम पर बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन, उनके राजनीतिक अनुभव और प्रभाव का इस्तेमाल भी पार्टी के लिए काम आ सकता है। लेकिन नरोत्तम को दिमनी में थोड़ी मेहनत और मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। मतदाताओं का भरोसा जीतना और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कदमताल करके चलने की रणनीति पर भी काम करना होगा। नरेंद्र सिंह तोमर की मदद से मिश्रा की राह आसान भी हो सकती है।

शाह के करीबियों में होती है मिश्रा की गिनती

सियासी जानकारों का कहना है कि पार्टी आलाकमान डॉ. नरोत्तम मिश्रा के अनुभव का हर हाल में फायदा उठाना चाहेगी। लेकिन, मध्यप्रदेश में उच्च सदन यानी विधान परिषद (एमएलसी) नहीं है। ऐसे में सदन तक पहुंचने के लिए सिर्फ विधानसभा का चुनाव लड़ना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए उनकी हार के बाद उप चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। नरोत्तम ग्वालियर-चंबल इलाके से आते हैं और वहां फिलहाल एकमात्र दिमनी सीट ही ऐसी है, जहां उपचुनाव की संभावना बन सकती है। मिश्रा की गिनती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में भी होती है।

ये जिम्मेदारी सौंप सकता है भाजपा आलाकमान

केंद्रीय संगठन में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद पर काबिज कर उनकी संगठनात्मक क्षमता का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा मिश्रा के मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

कमलनाथ व विजयवर्गीय के फर्जी वीडियो समेत डीपफेक पर इंदौर में 4 केस दर्ज

क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल के मुताबिक डीपफेक की सबसे ज्यादा शिकायतें विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुईं

डीपफेक की चिंता के बीच आपराधिक गैंग की सक्रियता बढ़ने लगी है। अभी तक बड़े राजनेता और सेलिब्रिटी ही इस तरह के फर्जी वीडियो बनाने वाले गिरोह के निशाने पर होते थे। चलन बढ़ा तो बड़े उद्योगपतियों को भी निशाना बनाया जाने लगा, परंतु अब तो स्थानीय स्तर पर डीपफेक का उपयोग बढ़ने लगा है। शहर में अब तक चार एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं। एक नेता अश्लील वीडियो के शिकार हुए हैं। इस नेता ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है।

क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल के मुताबिक डीपफेक की सबसे ज्यादा शिकायतें विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुईं। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित किया गया, जो लाड़ली लक्ष्मी योजना बंद करने से जुड़ा था। इस फर्जी वीडियो की अपराध शाखा में एफआइआर दर्ज की गई। कांग्रेस नेता राकेश यादव की शिकायत पर प्रकरण की साइबर सेल जांच में जुटी है। कनाड़िया थाने की पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फर्जी वीडियो जारी करने पर एफआइआर दर्ज की है। पुलिस सिर्फ बहुप्रसारित करने वालों का डाटा जुटा सकी है। वीडियो कहां बना इसके सबूत नहीं मिल पाए हैं। क्राइम ब्रांच ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का फर्जी वीडियो बनाने पर भी एफआइआर दर्ज की है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी का अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में भी एफआइआर दर्ज की।

कोडर - डिकोडर की मदद

साइबर एसपी जितेंद्रसिंह के मुताबिक डीपफेक बनाने वाला गिरोह डार्कनेट पर सक्रिय है। डार्कनेट पर अभी तक हथियार, मादक पदार्थ और एटीएम-क्रेडिट कार्ड की जानकारी बिक रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अब डार्कनेट पर भी फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक मिनट लंबे वीडियो के एवज में एक लाख रुपये तक लिए जा रहे हैं। यह काम दो स्तर पर होता है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया जाता है। इस टेक्नोलाजी में कोडर और डिकोडर की मदद ली जाती है। डिकोडर उस व्यक्ति के चहरे और हावभाव को परखता है, जिसका वीडियो बनाना है।

लोस चुनाव के लिए समीकरण साधने की कवायद...

भाजपा प्रभावशाली वर्ग को साधने की कर रही कोशिश

भाजपा शीर्ष नेतृत्व की मंशा है कि तीनों ही राज्यों में ऐसी सरकार बने, जिसमें आदिवासी, ओबीसी, महिला और युवा वर्ग को वरीयता दिए जाने का संदेश जाए। खासकर महिला मतदाताओं का पूरी तरह साथ बना रहे।

भाजपा नेतृत्व तीनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक-राजनीतिक समीकरण के लिहाज से सरकार की रूपरेखा तय करना चाहता है। सरकार के जरिये पार्टी की कोशिश इन राज्यों में हर प्रभावशाली वर्ग को साधने की है। इसी के सहारे नेतृत्व विपक्षी गठबंधन के ओबीसी कार्ड की काट के साथ अपनी दूसरी मुश्किलों को हल करना चाहता है।

पार्टी नेतृत्व की मंशा है कि तीनों ही राज्यों में ऐसी सरकार बने, जिसमें आदिवासी, ओबीसी, महिला व युवा वर्ग को वरीयता दिए जाने का संदेश जाए। खासकर महिला मतदाताओं का पूरी तरह साथ बना रहे। इसके लिए नतीजों के बाद से ही कई स्तर पर विमर्श जारी हैं। आखिरी फैसले से पहले क्षेत्रीय, सामाजिक, प्रशासनिक दक्षता व संगठन की भूमिका का आकलन होगा।

मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेताओं का केंद्रीय नेतृत्व से भेंट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। नरेंद्र तोमर और बाबा बालकनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से जहां भेंट की, वहीं रेणुका सिंह और वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। चूंकि सरकार की रूपरेखा तैयार नहीं हुई, इसलिए नतीजे के चौथे दिन भी पार्टी न तो पर्यवेक्षक तय कर पाई और न ही विधायक दल की बैठक की ही तारीख तय हो पाई है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।

विकसित भारत 2047 योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने किया लॉन्च, कहा-

विकसित भारत की दिशा में सब मिलकर करें काम

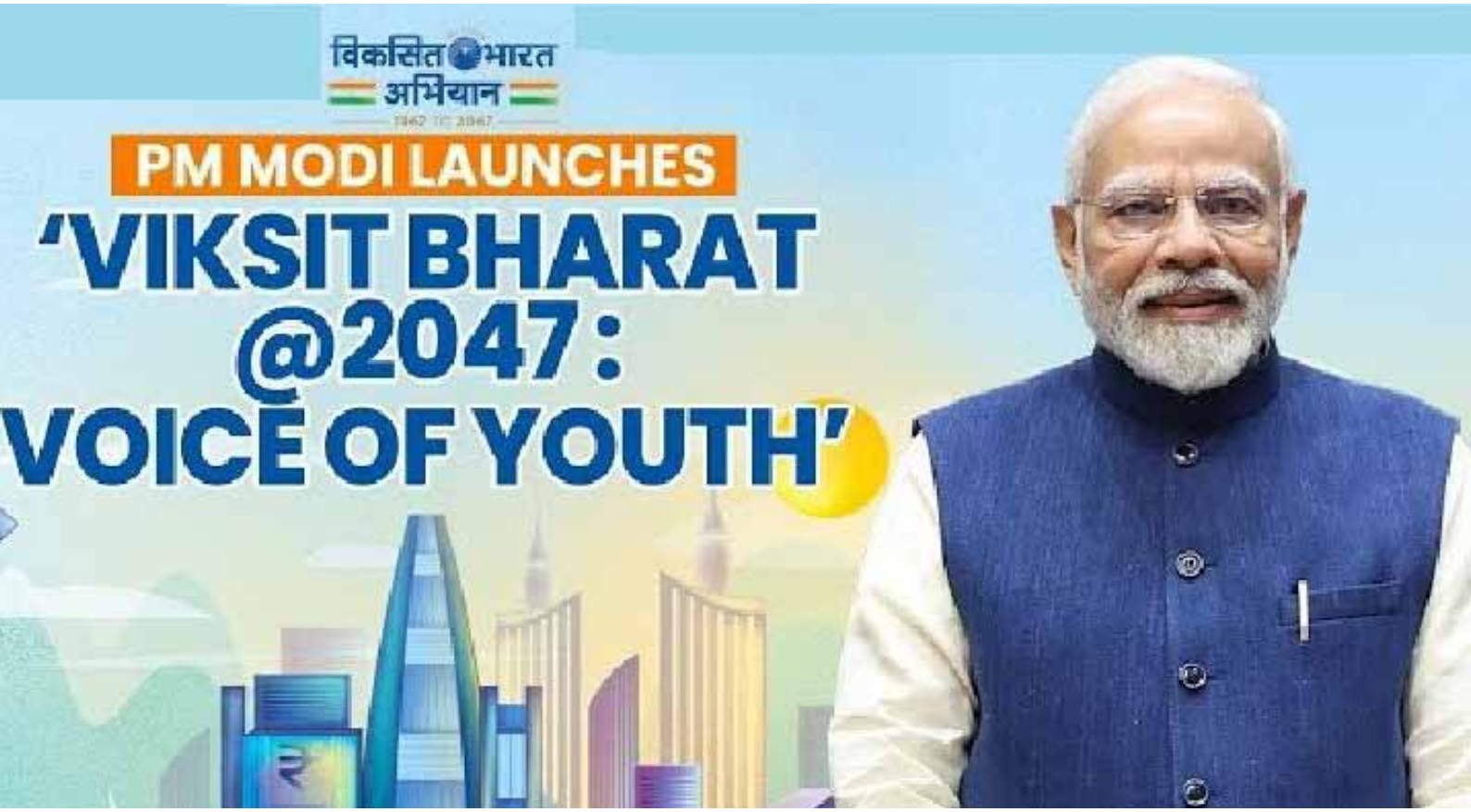

युवाओं को सफल ट्रेनिंग देने के लिए देश भर में वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपतियों और देश भर में राज भावनाओं में आयोजित कार्यशाला में संस्थाओं के प्रमुखों ने ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत@2047: युवाओं की आवाज योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया है। देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक इस योजना के जरिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के जरिए इस योजना को सफल बनाना जरुरी है। युवाओं को सफल ट्रेनिंग देने के लिए देश भर में वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपतियों और देश भर में राज भावनाओं में आयोजित कार्यशाला में संस्थाओं के प्रमुखों ने ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया है।

पीएम मोदी ने संबोधन में कही ये बातें

बता दें कि इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत@2047 एक बेहद अहम पहल है जिसका उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण की दिशा में युवाओं को एकीकृत करना है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन विकसित भारत के संकल्पों को लेकर काफी अहम है। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी राज्यपालों को विकसित भारत के निर्माण से संबंधित वर्कशॉप का सफल आयोजन करने पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों को एक मंच पर लगाएं हैं जिनपर देश की युवा शक्ति को दिशा देने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति और व्यक्तिगत विकास होता है तो ही राष्ट्र का भी निर्माण हो सकता है। आज के समय में भारत में व्यक्तित्व विकास अभियान बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने इस कार्यशाला के दौरान कहा कि भारत के इतिहास का ये वो दौर चल रहा है जब देश विकास की दिशा में लंबी छलांग लगा रहा है। हर ओर इस तरह विकास के कई उदाहरण देखने को मिल रहे है। ये भारत के लिए बिलकुल सही समय है, जब हर पल का लाभ उठाकर देश को विकासित करने की दिशा में काम करना चाहिए। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने तय समय में लंबी छलांग लगाकर विकास किया है। इस समय को अमर बनाने के लिए हर क्षण का लाभ उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में ये अमृतकाल उसी तरह का समय है जैसे की आमतौर पर परीक्षा के दिनों में होता है। छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन को लेकर तभी आत्मविश्वास से भरता है जब उसकी तैयारी होती है। अंतिम समय तक भी वो लगातार कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसे ही इस समय भी देश के हर नागरिक को परीक्षा की तरह ही हर क्षण अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करना है।

सड़कों के गड्ढे छीन रहे हैं लाखों जिंदगियां...

कमोबेश दुनिया के देशों में आज भी सड़कों पर गड्ढ़ों के कारण दुर्घटना से मौत के आंकड़ों में साल दर साल बढ़ोतरी ही होती जा रही है। केन्द्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तमाम सड़क हादसों में सबसे अधिक मौत सड़कों पर बने गड्ढ़ों के कारण हो रही है।

हालांकि आतंकवादी गतिविधियों में होने वाली जनहानि से दुनिया के देशों में सड़कों के गड्ढ़ों से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों से तुलना करना एक तरह से उचित नहीं माना जा सकता पर जिम्मेदारों की जरा-सी लापरवाही से सड़क के गड्ढों के कारण होने वाली मौतों का बढ़ता आंकड़ा गंभीर चिंता का कारण बन जाता है। हालांकि आतंकवादियों का उद्देश्य अलग होता हे वहीं सड़कों के गड्ढ़ों की मरम्मत कराकर ठीक करना तो हमारे हाथ में ही होता है। बात थोड़ी अजीब अवश्य लगेगी पर वास्तविकता तो यही है कि देश दुनिया में सड़कों के गड्ढे दुनिया की आतंकवादी गतिविधियों पर भारी पड़ रहे हैं। वैश्विक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो 2021 में आतंकवादी गतिविधियों के कारण 5226 लोग मारे गये। वहीं दूसरी और अकेले अमेरिका में ही 2021 में सड़कों के गड्ढ़ों के कारण 15 हजार से अधिक मारे गए। इसी तरह से इंग्लैण्ड में 1390, भारत में 3565 और रूस में 431 लोग मारे गए। आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों से यह कोई चार गुणा अधिक है। कमोबेश दुनिया के देशों में आज भी सड़कों पर गड्ढ़ों के कारण दुर्घटना से मौत के आंकड़ों में साल दर साल बढ़ोतरी ही होती जा रही है। केन्द्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तमाम सड़क हादसों में सबसे अधिक मौत सड़कों पर बने गड्ढ़ों के कारण हो रही है। अब सड़क में गड्ढ़ों के कारण मौत की जिम्मेदारी सरकार या स्थानीय प्रशासन से इतर किसी और को दी भी नहीं जा सकती। मौत को अलग कर भी दिया जाए तो सड़कों पर गड्ढ़ों से होने वाले अन्य नुकसान का ही विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि यह कोई छोटी-मोटी राजस्व हानि नहीं अपितु बड़े नुकसान से भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर चेन्नई में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार सड़क के गड्ढ़ों के कारण प्रतिदिन 75 करोड़ के राजस्व का नुकसान होता है। यह तो एक बानगी मात्र है और इससे आसानी से कयास लगाया जा सकता है कि सड़क के गड्ढ़े जनहानि और धन हानि दोनों के ही प्रमुख कारण हैं।

ऐसा नहीं है कि सरकारें या दुनिया के देश इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं हों पर जो नतीजे साल दर साल देखने को मिलते हैं वह अपने आप में गंभीर है। सड़क के गड्ढ़ों की वैश्विक गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि जानकारों को मानना है कि प्रतिवर्ष 15 जनवरी को राष्ट्रीय गड्ढ़ा दिवस मनाया जाता है। इंग्लैण्ड में गड्ढ़ों से होने वाले नुकसान पर नागरिकों को मुआवजा देने का प्रावधान है। दूसरी और

दुनिया के देशों द्वारा भी सड़कों के गड्ढ़ों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं व मौतों को लेकर बड़े-बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठियां, जनचेतना रैलियां होती रहती हैं तो सड़क निर्माण में लगे इंजीनियरों व अन्य कार्मिकों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भी साफ है कि गड्ढ़ों के जो प्रमुख कारण हैं वे भी किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मोटे मोटे रूप से कहा जाए तो सड़कों की खराब डिजाइन, हल्की सड़क निर्माण सामग्री, सड़क निर्माण मानकों की अनदेखी, सड़कों पर पानी भरने, रखरखाव व देखरेख में लापरवाही, ठेकेदारों व अधिकारियों की लालची प्रवृत्ति, सड़कों की मरम्मत कार्य में लापरवाही, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने, सड़कों पर पानी की सही निकासी नहीं होने और इसी तरह के कई कारण हैं जिनके चलते सड़कों पर गड्ढ़े बन जाते हैं। देखा जाए तो थोड़ी-सी अनदेखी, लापरवाही और छोटे से लालच के कारण यही सड़कें मौत का कारण बन जाती हैं। इसके साथ ही आम जन की परेशानी का कारण बनने के साथ ही सरकारी धन का नुकसान होता है वह अलग। केवल गड्ढ़ा होने से दुर्घटना में मौत ही नहीं अपितु कितना नुकसान होता है यह किसी से छिपा नहीं है। एक पक्ष यह भी कि गड्ढ़ों के कारण दुर्घटना के साथ अन्य होने वाले नुकसानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाहनों के कलपुर्जों, टायर आदि को नुकसान, सामान्य आदमी को भी धचकों से होने वाले पीठ आदि के दर्द, बीमार आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर, ईंधन का नुकसान, समय का नुकसान सहित अनेक ऐसे नुकसान हैं जिनकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती।

पिछले दिनों केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क निर्माण में होने वाली लापरवाही के लिए संबंधित इंजीनियर्स व अन्य को जिम्मेदार बनाने, समुचित रखरखाव, ड्रोन से निगरानी और लोगों को टोल नंबर पर शिकायत करने जैसी सुविधाएं या कदम उठाने की पहल की है। इसी तरह से यह प्रावधान भी कई राज्य सरकारों द्वारा किए गए हैं व किए जा रहे हैं कि निश्चित समय सीमा से पहले सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सड़क बनाने वाले ठेकेदार की होगी। पर इसकी कितनी पालना हो रही है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है बल्कि देखने में तो यही आता है कि एक बार सड़क बन जाने के बाद उसका कोई धनी धोरी ही दिखाई नहीं देता और फिर कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है और उसके कारण बवंडर मच जाता है तब जाकर नींद खुलती है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आज देश दुनिया में एक से एक नई तकनीक आ गई है। इसमें सड़क निर्माण की तकनीक भी शामिल है। पानी भरने वाले स्थानों पर सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनने लगी हैं पर ढाक के वही तीन पात दिखाई देते हैं और सड़कों की गुणवत्ता पर आए दिन प्रश्न उठते रहते हैं।

हालांकि यह प्रश्न उठाने की बात नहीं बल्कि सामने दिखने वाली बात है। हालात यहां तक हो गए हैं कि टोल सड़कों पर भी सड़कों के हालात अब ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। आखिर गड्ढों या अन्य कारणों से किसी भी तरह की जनहानि या धनहानि होती है तो वह राष्ट्रीय नुकसान ही है।

इसलिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी व गैरसरकारी संस्थाओं को आगे आना होगा और कम से कम कम सड़कों के गड्ढ़ों को तो मौत का कारण नहीं बनने दिया जाना चाहिए। सोचना यह होगा कि किसी जिम्मेदार की छोटी-सी लापरवाही किसी परिवार पर कितना कहर बन कर आती है। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ ही राज्यों के सड़क परिवहन मंत्रालयों खासतौर से सड़क निर्माण में जुटी संस्थाओं को दुर्घटनामुक्त सड़कों के निर्माण के साथ ही सड़कों के रखरखाव के प्रति ध्यान देना होगा।

पीओके हमेशा से हमारा है

शाह बोले- देश की 1 इंच जमीन भी जाने नहीं देंगे

शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस की और कहा कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में दो विधेयक - जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू कश्मीर को देखते थे और उन्होंने इसे बीच मझधार में ही छोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू ने माना था कि कश्मीर को लेकर उनसे गलती हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं आतंकवादियों के लिए बिल्कुल नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पत्थरबाजी करने वाले हाथों में अब लैपटॉप है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीओके हमेशा से भारत का है। उन्होंने कहा कि 1 इंच भी देश का जमीन हम जाने नहीं देंगे। कांग्रेस ने 40 साल तक गलतियां की है।

अमित शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस की और कहा कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीईओ को अनुमोदना दिया, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कानून को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहस हुई, पांच जजों की बेंच बनी और आज इस पर फैसला भी आ गया। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये (कांग्रेसी) कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। मैं इनको नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है।

गृह मंत्री ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग, ये जो नाम है ये किसी भी नागरिक की dignity को बहुत हर्ट करने वाले है। मैं आज जो दो बिल लेकर आया हूं उसमें से पहले बिल में कमजोर और वंचित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग ये नाम जोड़ने का फैसला लिया है। दूसरा बिल- जम्मू कश्मीर में 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई और 89 तक चरम सीमा तक पहुंचा। जिस कारण से कश्मीरी पंडित और सिख भाई घाटी छोड़कर पूरे देश में बिखर गए। सभी राज्यों ने कश्मीरियों को गले लगाया। जम्मू कश्मीर में वर्षों से अलग अलग जगहों से विस्थापित हुए कश्मीरी लोगों को सम्मान देने के लिए ये बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक तंग नजरियों का सवाल है, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को भी अपना बड़ा दिल दिखाने के लिए हमारी जमीन का एक हिस्सा देने का अधिकार नहीं है। शाह ने कहा कि अभी कहा गया कि नेहरू जी के कारण कश्मीर यहां है। मैं आज कहना चाहता हूं जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उन्हें मालूम होगा। हैदराबाद में इससे बड़ी समस्या थी क्या नेहरू जी गए थे सुलझाने? जवाहर लाल नेहरू ने एक ही काम देखा था और उसे अधूरा छोड़कर आ गए। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि कश्मीर के विलय में इसलिए देरी हुई थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था और इस कारण विलय में देरी हुई और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। जो लोग कहते हैं कि यह नेहरू के कारण है कि कश्मीर अभी भी हमारे पास है, उनके लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य पर विचार करना आवश्यक है, जैसे कि हैदराबाद का मामला। नेहरू ने हैदराबाद, जूनागढ़, लक्षद्वीप या जोधपुर में हस्तक्षेप नहीं किया। उनका ध्यान सिर्फ कश्मीर पर था और वहां भी उन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया।

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा

अमिताभ, अंबानी, अडाणी, सचिन, कोहली समेत सात हजार लोगों को निमंत्रण...

निमंत्रण पत्र में लिखा है, आपको विदित ही हैं कि लंबे संघर्ष के पश्चात, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080, सोमवार (22 जनवरी 2024) को गर्भगृह में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी...

अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने की कगार पर है और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। भगवान रामलला की कौन-सी मूर्ति मंदिर में स्थापित होगी इसका चयन 15 दिसंबर को किया जायेगा। इस बीच, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण भेजे जाने का काम भी चल रहा है। हम आपको बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और उद्योगपति मुकेश अंबानी सहित करीब सात हजार लोगों को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया है। ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल (भगवान राम) और देवी सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 22 जनवरी, 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। ट्रस्ट ने 3000 वीवीआईपी सहित 7,000 लोगों को आमंत्रण भेजा है। कार्यक्रम में 1992 में मारे गए

कारसेवकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित वीवीआईपी लोगों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु राम देव, उद्योगपति रतन टाटा, उद्योगपति गौतम अडाणी भी शामिल हैं। ट्रस्ट ने देशभर से 4000 संतों को भी आमंत्रित किया है जो राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे। इस बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, ''प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 50 देशों से एक-एक प्रतिनिधि बुलाने का प्रयास है। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कारसेवक परिवारों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है।'' उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया हैं। चंपत राय ने बताया कि इसके अलावा संतों, पुजारियों, शंकराचार्यों, धार्मिक नेताओं, पूर्व नौकरशाहों, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, वकीलों, संगीतकारों और पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है।

इस बीच, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा, ''हमने उन पत्रकारों को भी आमंत्रित किया है, जिन्होंने अपने समाचार पत्रों, लेखों और रिपोर्टिंग के माध्यम से हमारे राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था, उनके (पत्रकारों के) बिना, राम मंदिर का यह संघर्ष अधूरा था।'' शरद शर्मा ने बताया कि ''वीवीआईपी को बार कोड पास के जरिए प्रवेश मिलेगा। आमंत्रित 7000 लोगों में से लगभग 4,000 देश भर से आए धार्मिक नेता होंगे। बाकी 3000 विभिन्न क्षेत्रों के वीवीआईपी होंगे। समारोह से पहले आमंत्रित लोगों के साथ एक लिंक साझा किया जाएगा। एक बार जब वे लिंक के साथ पंजीकृत हो जाएंगे, तो कोड उत्पन्न होगा जो प्रवेश पास के रूप में कार्य करेगा।''

हम आपको बता दें कि निमंत्रण पत्र में लिखा है, ''आपको विदित ही हैं कि लंबे संघर्ष के पश्चात, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080, सोमवार (22 जनवरी 2024) को गर्भगृह में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारी प्रबल इच्छा है कि आप इस पुनीत अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहकर प्राण-प्रतिष्ठा के साक्षी बनें और इस महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बढ़ाएं।'' निमंत्रण पर राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के हस्ताक्षर हैं।

रामलला की मूर्ति के बारे में चंपत राय ने कहा, ''राम मंदिर में रामलला पांच साल के बालक के रूप में विराजमान होंगे। इसके लिए दो चट्टानों से तीन मूर्तियां बनाई जा रही हैं जिनमें से एक चट्टान कर्नाटक से दूसरी राजस्थान से लाई गई है।'' उन्होंने कहा, ''मूर्तियां 90 प्रतिशत तैयार हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राण-प्रतिष्ठा के लिए सबसे आकर्षक मूर्ति का चयन किया जाएगा।'' बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए रामलला की मूर्ति 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि रामलला (भगवान राम के बाल स्वरूप) की तीन मूर्तियां बनवाई जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर न्यास की धार्मिक समिति 15 दिसंबर को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का चयन करेगी। मूर्तियां कर्नाटक और राजस्थान के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें कर्नाटक के गणेश भट्ट और अरुण योगीराज के साथ जयपुर के कलाकार सत्यनारायण पांडे भी शामिल हैं।

दूसरी ओर, देशभर से लोग रामलला के लिए अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ सामान लेकर आ रहे हैं जो दर्शा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने को लेकर देशभर में कितना उत्साह है। इसी क्रम में राजस्थान से 600 किलो देशी घी लेकर पहुँचे राम भक्त का ट्रस्ट के पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया।

पंप हाऊस-अस्पतालों की बिजली गुल होने की नौबत, नोटिस जारी

सरकारी दफ्तरों का 300 करोड़ का बिल बकाया

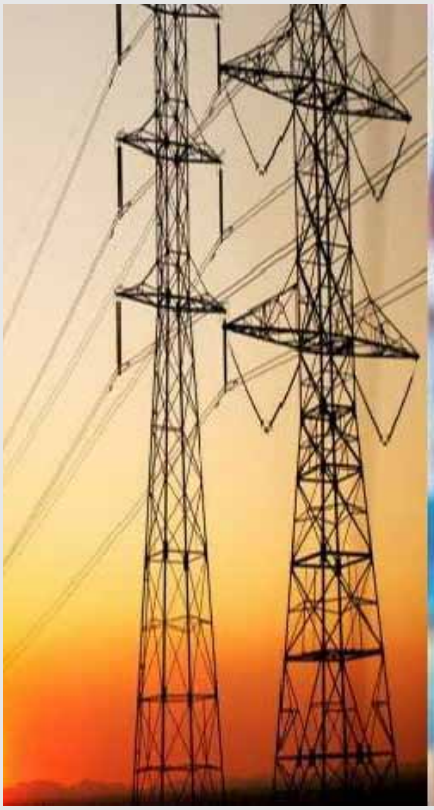

वित्त विभाग के अफसरों ने राजस्थान के सरकारी खजाने को किस तरह लूटा इसका खुलासा अब हो रहा है। सरकारी दफ्तरों के रोजमर्रा के खर्चों के 300 करोड़ के बिल बकाया चल रहे हैं। हालात ये हैं कि सरकारी अस्पताल से लेकर पानी सप्लाई करने वाले पंप हाऊसों के बिजली कनेक्शन काटने की नौबत आ गई है।

सरकारी खजाने की रखवाली का जिम्मा संभालने वाले वित्त विभाग के अफसरों ने राजस्थान को किस कदर कर्ज के दलदल में धकेला है, इसकी बानगी अब सामने आ रही है। सरकारी दफ्तरों में रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। दफ्तरों के 300 करोड़ रुपए के बिल पेंडिंग चल रहे हैं। हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं कि पूरे जयपुर को पानी सप्लाई करने वाले पंप हाऊसों के बिजली कनेक्शन काटने के लिए विद्युत विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जवाहर सर्किल पंप हाऊस, मानसरोवर पंप हाऊस, सेंट्रल पार्क पंप हाऊस, बालाबाला पंप हाऊस, और खोनागौरियान पंप हाऊस के मिलाकर 3 करोड़ 19 लाख रुपए के बिजली के बिल 20 नवंबर से बकाया चल रहे हैं।

अधिकारी ने पत्र लिखकर चेताया : पीएचईडी के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने 11 दिसंबर को कोषाधिकारी-कोष कार्यालय को पत्र लिखकर कहा है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से कनेक्शन काटे जाने के नोटिस प्राप्त हुए हैं। अगर, कनेक्शन कट गए तो बीसलपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत समस्त जयपुर की सप्लाई बाधित हो सकती है।

जिला अस्पतालों को भी बिजली काटने का नोटिस मिला

स्थितियां बेहद गंभीर है। जिला अस्पतालों को भी विद्युत कनेक्शन काटने के नोटिस मिल रहे हैं। बाड़मेर जिला अस्पताल के अधीक्षक ने भी कोषाधिकारी-कोष कार्यालय, बाड़मेर को पत्र लिखकर कहा है कि यदि अस्पताल के बिजली कनेक्शन कट गए तो इससे उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। अस्पताल को 21 नवंबर को 19 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल मिला था जिसे जमा करवाने के लिए उसी दिन कोष कार्यालय भेज दिया गया था। बिज जमा करवाने की अंतिम तिथि 24 नवंबर थी। लेकिन वित्त विभाग की ओर से रकम ईसीएस ही नहीं की गई।

सम्मेलन में डब्ल्यूएमओ ने पेश की रिपोर्ट

जलवायु परिवर्तन के बड़े असर से भारत में बढ़ रही गर्मी व बारिश

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन (कॉप-28) में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने भारत पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिगड़ते जलवायु परिवर्तन के चलते 2011 से 2020 के दशक को औसत से ज्यादा गर्मी और सर्वाधिक बारिश वाला बताया गया। रिपोर्ट के डराने वाले आंकड़ों में बताया गया कि इस अवधि में जलवायु परिवर्तन की दर चिंताजनक रूप से बढ़ी जो रिकॉर्ड में सबसे अधिक रही।

संयुक्त राष्ट्र के डब्ल्यूएमओ ने मौसम, जलवायु व जल संसाधन पर शोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2011-20 का दशक उत्तर-पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, चीन व अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट के लिए सबसे गर्म रहा है। वहीं, ठंडे दिनों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले दशक में 1961-1990 के दशकों की तुलना में ठंडे दिन 40% घटे हैं। भारत में बाढ़ की समस्या भी बढ़ गई है। जून 2013 में भारी बारिश, पहाड़ों की बर्फ पिघलने और ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं।

लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ा : डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2020 के बीच भीषण बाढ़ से भारत में 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके अलावा गर्मी से बचाव के लिए इसका जीवनयापन पर बड़ा असर पड़ा है। इससे लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ रहा है।

गुजरात की दो महिलाओं ने पेश किए पारंपरिक समाधान

देसी परिधान पहन संगीताबेन राठौड़ व जसुमतिबेन जेठाभाई परमार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पारंपरिक समाधानों के साथ जलवायु सम्मेलन में दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। इससे पहले कभी अपने गृह राज्य गुजरात से बाहर नहीं निकलीं अरावली की राठौड़ और जेतापुर की परमार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान पेश किए। अपने पारंपरिक ज्ञान के बलबूते वे नीम की पत्तियों और गोमूत्र का इस्तेमाल कर जैविक खाद एवं कीटनाशक बना रही हैं, जिसने न केवल वर्षों तक उनकी फसलों को बचाकर रखा है, बल्कि पूरे भारत में महिला किसान इसे अपना रही हैं। इससे रासायनिक खाद का एक सतत विकल्प मिला है।

भारत को गति बनाए रखना जरूरी : यूएनडीपी

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत के जलवायु प्रमुख डॉ. आशीष चतुर्वेदी ने कहा कि भारत को वैश्विक जलवायु कार्रवाई की दिशा में यहां संयुक्त राष्ट्र कॉप-28 शिखर सम्मेलन में अपनी गति और पैरवी के प्रयासों को जारी रखना जरूरी है। उन्होंने विकसित देशों से अधिक प्रतिबद्धता और वित्त पोषण की मांग को भी जरूरी बताया।

कॉप-33 की मेजबानी के लिए भारत सबसे सक्षम : यूएई

भारत में संयुक्त अरब अमरीत (यूएई) के राजदूत अब्दुलनासिर अलशाली ने देश की संगठनात्मक शक्ति पर विश्वास जताते हुए कहा कि भारत कॉप-33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में सक्षम है। यदि कोई देश इस सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है तो वह भारत है।

सनातन संस्कृति ही भारत में कुटुंब व्यवस्था को जीवंत बनाये हुए है...

कुल मिलाकर यह सनातन संस्कृति के संस्कार ही हैं जो भारत में आज भी कुटुंब व्यवस्था को जीवित रखे हुए हैं। संयुक्त परिवार सामान्यतः केवल भारत में ही दिखाई देते हैं, जहां बुजुर्गों की देखभाल इन संयुक्त परिवारों में बहुत ही सहज तरीके से होती है।

भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार पवित्र शादियों के धार्मिक संस्कारों के माध्यम से दो आत्माओं का मिलन कराया जाता है। कहा तो यहां तक भी जाता है कि दूल्हा और दुल्हन शादी के धार्मिक संस्कारों के माध्यम से सात जन्मों तक के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। इसलिए, शादी के समय विभिन्न अध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांसारिक संस्कारों को सम्पन्न कराने के लिए समाज के गणमान्य नागरिकों, नाते रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों को साथ लेकर विभिन्न प्रकार के भव्य आयोजन सम्पन्न किए जाते हैं। इन आयोजनों में विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं एवं आजकल तो ऐसे शुभ अवसरों पर भारी मात्रा में व्यय भी किया जा रहा है। शादी के विभिन्न आयोजनों पर किए जाने वाले भारी भरकम खर्च से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।

भारत में नवम्बर 2023 माह से लेकर आगामी लगभग 4 माह के दौरान 38 लाख से अधिक शादियों के आयोजन सम्पन्न होने जा रहे हैं। केवल 4 माह की इस अवधि में लगभग 4.75 लाख करोड़ की राशि का व्यय होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 35 लाख शादियों पर 3.75 लाख करोड़ रुपए की राशि का व्यय हुआ था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार, भारत में इस वर्ष शादियों के मौसम में सबसे अधिक खर्च करने का विश्व रिकार्ड बनाया जा सकता है। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष एक लाख करोड़ रुपए अधिक राशि शादियों पर खर्च होने जा रही है। शादी के विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च के सम्बंध में भी अनुमान लगाए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष नए कपड़े और नई ज्वेलरी को खरीदने की मद पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने वाली है, मेहमानों की खातिरदारी पर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने जा रही है, शादी समारोह से जुड़े कार्यक्रमों पर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने जा रही है। विश्व का कोई भी देश शादियों के मौसम में इतनी भारी भरकम राशि का खर्च नहीं करता दिखाई दे रहा है क्योंकि अन्य देशों में शादी के समारोहों पर इतना खर्च किया ही नहीं जाता है। यह तो भारतीय सनातन संस्कृति ही है जिसके अंतर्गत शादी के समय विभिन प्रकार के संस्कार सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कई प्रकार के आयोजन सम्पन्न किए जाते हैं। आज विकसित देशों में तो विवाह नामक संस्था उपलब्ध ही नहीं है और "लव मैरिज" नामक रिवाज का पालन किया जा रहा है। साथ ही अब तो बगैर विवाह के "लिव इन रिलेशन" नामक रिवाज ही चल पड़ा है। विकसित देशों के युवा इस प्रकार के रिवाजों के चलते बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं और कुछ समय पश्चात ही आपस में रिश्तों को "तलाक" का रूप दे देते हैं। यदि इस बीच किसी जोड़े को बच्चा हो भी जाता है तो उसे "सिंगल पेरेंट" के रिवाज के तहत केवल मां के पास ही रहना होता है। इस प्रकार वह बच्चा अपने पिता के प्यार से वंचित रहता है और उस बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। इन्हीं कारणों के चलते आज विश्व के कई देशों में बुजुर्गों की संख्या तो बढ़ती जा रही है परंतु युवाओं की संख्या कम होती जा रही है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।

अतः कुल मिलाकर यह सनातन संस्कृति के संस्कार ही हैं जो भारत में आज भी कुटुंब व्यवस्था को जीवित रखे हुए हैं। संयुक्त परिवार सामान्यतः केवल भारत में ही दिखाई देते हैं, जहां बुजुर्गों की देखभाल इन संयुक्त परिवारों में बहुत ही सहज तरीके से होती है। अन्यथा, विकसित देशों में चूंकि संयुक्त परिवार का चलन नहीं के बराबर है अतः बुजुर्गों की देखभाल इन देशों की सरकार को "सोशल बेनीफिट्स" योजना के अंतर्गत करनी होती है। आज कुछ देशों में तो "सोशल बेनीफिट्स" की मद पर इतना अधिक खर्च होने लगा है कि इन देशों की बजट व्यवस्था ही भारी दबाव में आ गई है। इसके ठीक विपरीत, भारत में विभिन्न त्यौहार भी बड़े ही उत्साह से मनाए जाते है जिसके कारण भारत में सामाजिक तानाबाना ठीक बना हुआ है। इसी सामाजिक तानेबाने के ठीक अवस्था में रहने के चलते ही इस वर्ष, दीपावली एवं धनतेरस के त्यौहारी मौसम में भारत में 3.75 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। साथ ही, केवल करवा चौथ के दिन 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार सम्पन्न हुआ था।

भारत में त्यौहारी मौसम में अक्टोबर 2023 माह में 23 लाख वाहनों की बिक्री हुई है। 4 लाख चारपहिया वाहन एवं 19 लाख दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। आने वाले शादियों के मौसम में भी इस वर्ष वाहनों की जबरदस्त बिक्री होने की सम्भावना है। उक्त वर्णित कारणों के चलते ही भारत में तेजी से गरीबी एवं बेरोजगारी भी कम हो रही है। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2022-23 में दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी की दर 32.8 प्रतिशत रही है और ईरान में 9.4 प्रतिशत, ब्राजील में 8.3 प्रतिशत, पाकिस्तान में 8.5 प्रतिशत, फ्रान्स में 7.4 प्रतिशत, इटली में 7.9 प्रतिशत, चीन में 5.3 प्रतिशत, ब्रिटेन में 4.2 प्रतिशत और अमेरिका में 4 प्रतिशत बेरोजगारी की दर पाई गई है। उक्त आंकड़ों के विपरीत भारत में इस अवधि के दौरान बेरोजगारी की दर में बहुत कमी दृष्टिगोचर हुई है।

अवैध आप्रवासन के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कानून पेश-सुनक

सुनक ने कहा कि भले ही मैं एक प्रवासी का बेटा हूं लेकिन मेरे माता-पिता कानूनी रूप से ब्रिटेन आए थे। अप्रवासियों के बच्चे के रूप में मैं समझ सकता हूं कि लोग यहां क्यों आना चाहते हैं।

ब्रिटेन में आप्रवासन एक बहुत बडी समस्या बनती जा रही है। इसे रोकने के लिए सरकार भी कई फैसले ले रही है। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले ले रहे हैं। अवैध प्रवास समाप्त होना चाहिए।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि हमारा नया विधेयक अब तक का सबसे सख्त अवैध आव्रजन विरोधी कानून है। इस विधेयक के कारण देश में आने वाले लोगों को संसद नियंत्रित करेगी, न कि आपराधिक गिरोह या कोई विदेशी अदालतें। सुनक ने कहा कि भले ही मैं एक प्रवासी का बेटा हूं लेकिन मेरे माता-पिता कानूनी रूप से ब्रिटेन आए थे। हमारे यहां आपराधिक गिरोह कमजोर लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अप्रवासियों के बच्चे के रूप में मैं समझ सकता हूं कि लोग यहां क्यों आना चाहते हैं।

यह है नया कानून : हाल ही में, ब्रिटेन के गृह सचिव जेम्स क्लेवरली ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया था कि नए नियमों के तहत स्वास्थ्य वीजा पर ब्रिटेन आने वाले डॉक्टर अब अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने साथ नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा, कुशल श्रमिक वीजा पॉलिस के तहत आवेदकों के लिए वर्तमान सीमा जीबीपी 26,200 को बढ़ाकर जीबीपी 38,700 कर दिया गया है। वहीं, पारिवारिक वीजा श्रेणी के तहत आवेदन करने वालों को जीबीपी 18,600 है। आव्रजन नीति निष्पक्ष, सुसंगत, कानूनी और टिकाऊ होनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि छात्रों के आश्रितों पर रोक लगाने के कारण 3,00,000 कम लोग ब्रिटेन आएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कहना है कि आव्रजन दर को कम करने की पॉलिसी कड़ी कार्रवाई है। आप्रवासन नीति से ब्रिटेन को लाभ होगा।

ब्रिटेन के वीजा आवेदकों में सबसे अधिक भारतीय

ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार, ब्रिटेन में दूसरे देशों से आने वाले डॉक्टर, पेशेवरों, कुशल श्रमिकों और विदेशी छात्रों में सबसे अधिक दबदबा भारत का है। स्वास्थ्य वीजा के लिए भारतीय आवेदकों की संख्या में 76 फीसदी की बढ़त हुई है। कुशल श्रमिकों की संख्या में 11 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई है। छात्र वीजा के आवेदकों में 43 फीसदी भारतीय हैं।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य देश बना हंगरी

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हंगरी 96वां सदस्य देश बन गया है। बता दें इस गठबंधन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्त्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। हंगरी के गठबंधन में शामिल की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। हंगरी के राजदूत इस्तवान सज़ाबो और विदेश मंत्रालय के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी), आर्थिक संबंध और विकास प्रशासन भागीदारी (ईआर और डीपीए) पी कुमारन के बीच बैठक के दौरान हंगरी को अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा गया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि हंगरी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। बता दें पिछले माह चिली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना था। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता हैं। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य-उन्मुख, सदस्य-संचालित, सहयोगी मंच है।

इसी वर्ष 31 अक्तूबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी बैठक आयोजित की गई थी। आईएसए के महानिदेशक अजय माथुर ने कहा था कि इस वर्ष सौर ऊर्जा में निवेश 380 अरब डॉलर होने की उम्मीद है क्योंकि पिछले वर्ष 310 अरब डॉलर का निवेश हुआ था। साथ ही कहा था कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) दुनिया भर में परियोजनाओं में 9.5 गीगावॉट सौर ऊर्जा की वृद्धि का समर्थन कर रहा है।

तीन रॉकेटों से अहम मिशनों को अंतरिक्ष में भेजेगी स्पेस एजेंसी

इसरो की कारोबारी शाखा न्यू स्पेस इंडिया लि. (एनएसआईएल) के कारोबारी करार के तहत 20 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होंगे। ये जीसैट उपग्रह संचार के काम आएंगे। दोबारा उपयोग होने वाले रॉकेट के दो परीक्षणों से ऑटोनॉमस रनवे लैंडिंग प्रणाली परखी जाएगी।

अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने के लिहाज से साल 2024 भारत के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। इस दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तीन प्रमुख रॉकेटों से अहम मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (एलवीएम-3) से एक प्रक्षेपण होगा। वहीं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) के जरिये छह और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) के जरिये तीन मिशन भेजे जाएंगे। पीएमओ में केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया, कुछ अन्य मिशन भी अंतरिक्ष में भेजने की योजना है।

देश की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने वाला उपग्रह नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी) की तीसरी विकास उड़ान में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत दो मानव रहित उड़ानों की भी योजना है। मानव के साथ अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता की पुष्टि होगी और असल उड़ान के ऑर्बिट मॉड्यूल की जांच की जाएगी। गगनयान के लिए ही सब-ऑर्बिट मिशन भी परीक्षण रॉकेट के जरिये भेजने की योजना है। इससे गगनयान की क्रू-एस्केप प्रणाली परखी जाएगी।

20 सैटेलाइट होंगे लॉन्च

इसरो की कारोबारी शाखा न्यू स्पेस इंडिया लि. (एनएसआईएल) के कारोबारी करार के तहत 20 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होंगे। ये जीसैट उपग्रह संचार के काम आएंगे। दोबारा उपयोग होने वाले रॉकेट के दो परीक्षणों से ऑटोनॉमस रनवे लैंडिंग प्रणाली परखी जाएगी।

रॉकेटों के प्रमुख मिशन

पीएसएलवी के मिशन : जो 6 मिशन भेजे जाने हैं, उनमें एक-एक अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह व पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह और दो-दो तकनीकी प्रदर्शन मिशन व एनएसआईएल के व्यावसायिक मिशन हैं।

जीएसएलवी के मिशन : इस बाहुबली रॉकेट के जरिये मौसम-विज्ञान, दिशा प्रदर्शक उपग्रह और नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट (निसार) भेजे जाएंगे।

एलएमवी 3 के मिशन : एनएसआईएल के व्यावसायिक मिशन भेजने की योजना है।

एक साल में 1000 मरीजों को ब्लड कैंसर से मिलेगी मुक्ति

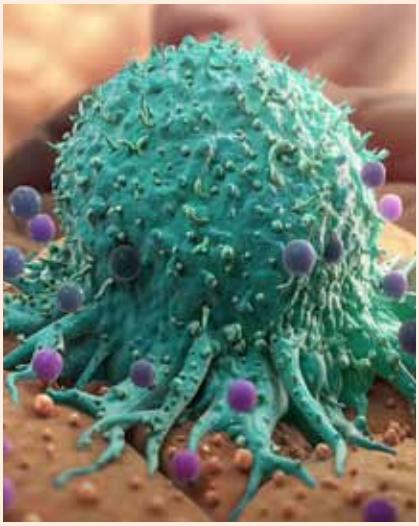

तकनीक कैंसर मरीज के इम्यून सेल्स पर आधारित है। सीएआर-टी थेरेपी में मरीज से उसके इम्यून सेल्स लिए जाते हैं और फिर आनुवंशिक रूप से प्रयोगशाला में इंजीनियर करते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो मरीज के सेल्स को कैंसर से लड़ने लायक बनाते हैं।

सरकार से अनुमति मिलने के करीब महीने भर बाद ब्लड कैंसर को खत्म करने वाली चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (सीएआर)-टी सेल थेरेपी अस्पतालों तक पहुंच गई है। देश के 15 अस्पतालों में इस थेरेपी को शुरू किया है, जहां अगले एक साल के भीतर 1,000 मरीजों को ब्लड कैंसर से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर भारत में इस तकनीक के लिए मैक्स हेल्थकेयर ने करार किया है। यहां थेरेपी लेने के लिए दो मरीजों ने अपना पंजीयन भी कराया है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने लिम्फोमा और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर पर अपना अध्ययन शुरू किया और 2021 में सीएआर-टी सेल थेरेपी को क्लीनिकल ट्रायल तक लेकर आए। मुंबई स्थित टाटा कैंसर अस्पताल सहित देश के कई चिकित्सा संस्थानों में क्लीनिकल परीक्षण में यह थेरेपी न सिर्फ सुरक्षित बल्कि 80% से ज्यादा असरदार मिली है। इन साक्ष्यों के आधार पर बीते 12 अक्तूबर को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस थेरेपी को देश के अस्पतालों तक पहुंचाने की अनुमित दी। इस थेरेपी के लिए सीएआर-टी कोशिकाओं की सोर्सिंग आईआईटी बॉम्बे की इनक्यूबेटेड कंपनी इम्यूनोएक्ट के सहयोग से की जाती है। देश के 15 अस्पतालों के साथ करार किया है।यह तकनीक कैंसर मरीज के इम्यून सेल्स पर आधारित है। सीएआर-टी थेरेपी में मरीज से उसके इम्यून सेल्स लिए जाते हैं और फिर आनुवंशिक रूप से प्रयोगशाला में इंजीनियर करते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो मरीज के सेल्स को कैंसर से लड़ने लायक बनाते हैं। एक बार सेल्स कैंसर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें वापस अस्पताल में भर्ती मरीज में प्रवेश करा दिया जाता है।

तीनों सेनाओं की ताकत में भी कोसों दूर विरोधी

भारत दुनिया की चौथी सैन्य शक्ति तो कनाडा 27वीं...

ग्लोबल फायरपावर की 'सैन्य ताकत सूची 2023' के अनुसार, 145 देशों में अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। इस सूची में रूस और चीन के बाद भारत का चौथा स्थान है। वहीं कनाडा की बात करें तो इसकी रैंक 27वीं है।

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है और आतंकियों के लिए इसे सुरक्षित अड्डा न बनने देने की सलाह भी दी है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है और आतंकियों के लिए इसे सुरक्षित अड्डा न बनने देने की सलाह भी दी है। दो देशों के बीच जारी कूटनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। जब भी दो देशों में तनाव होता है, तो उनके ताकत की चर्चा जरूर होती है। यही ताकत ही होती है जो दुनिया के देशों से उसको समर्थन दिलाती है। लिहाजा हम आपको बताते हैं भारत-कनाडा की सैन्य ताकत क्या है?

सैन्य ताकत : सैन्य शक्ति के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी पर नजर रखने वाली डाटा वेबसाइट ग्लोबल फायरपावर ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैनिकों की सूची जारी की थी। 'सैन्य ताकत सूची 2023' के अनुसार, 145 देशों में अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। इस सूची में रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, भारत का इस सूची में चौथा स्थान है। हमारे देश का एनेक्स स्कोर 0.1025 है जहां 0.0000 का स्कोर 'परफेक्ट' माना जाता है। वहीं कनाडा की बात करें तो यह भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। हालिया सूची में 145 देशों में से कनाडा की रैंक 27वीं है। इसका इंडेक्स स्कोर भारत से बहुत कम महज 0.3956 ही है।

मैनपॉवर : ग्लोबल फायरपावर के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सैन्य सेवा के लिए करीब 37 फीसदी आबादी उपयुक्त है। 2,36,23,837 भारतीय हर साल सैन्य आयु तक पहुंचते हैं। देश में अनुमानित सैन्यकर्मियों की संख्या 51,32,000 है। इसमें से 14,50,000 सैन्य कर्मी हैं जबकि रिजर्व कर्मी 11,55,000 हैं। भारत में अर्धसैनिक बलों की संख्या 25,27,000 है। वहीं सेना में 21,97,117 जवान हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा नौसेना और वायुसेना के कर्मियों की संख्या क्रमशः 1,42,252 और 3,10,575 है। कनाडा के मैनपॉवर की बात करें तो इसमें भी यह भारत से काफी पीछे है। इसकी कुल आबादी के करीब 35 फीसदी लोग ही सैन्य ताकत का हिस्सा बनने की योग्यता रखते हैं। यहां सालाना 4,20,559 लोग सेना में भर्ती होने के लिए काबिल होते हैं। कनाडा में कुल 94,500 सशस्त्र सैन्यकर्मी हैं। इनमें से 70,000 सक्रिय कर्मी हैं जबकि रिजर्व कर्मी 19,000 हैं। यहां अर्धसैनिक बल 5,500, वायु सेना कर्मी 15,620, सैन्य कर्मी 42,000 और नौसेना कर्मी 15,700 हैं।

हवाई ताकत : ग्लोबल फायरपावर के मुताबिक, देश की वायुसेना की ताकत आकें तो भारत के पास 2,210 विमानों का स्टॉक है। हमारे पास 577 लड़ाकू विमान हैं, जबकि आक्रमण विमान बेड़े का स्टॉक 130 है। हमारे परिवहन बेड़े की ताकत 98 है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास प्रशिक्षक विमान 353, विशेष-मिशन विमान 73, टैंकर बेड़ा 6, हेलीकॉप्टर 807 और आक्रमण हेलीकॉप्टर 36 हैं। कनाडा की हवाई ताकत पर गौर करें तो इसमें भी देश भारत से काफी पीछे है। इसके पास 376 विमान वाहक जबकि 63 लड़ाकू विमान हैं। जहां भारत के पास 130 आक्रमण विमान बेड़े हैं तो वहीं कनाडा के पास एक भी नहीं है। इसके अलावा कनाडा के पास परिवहन बेड़े 28, प्रशिक्षक विमान 132, विशेष-मिशन विमान 27, हेलीकॉप्टर 120 और टैंकर बेड़े छह हैं। भारतीय वायुसेना के पास जहां आक्रमण हेलीकॉप्टर 36 हैं वहीं कनाडाई खेमा इसमें निल है।

जमीनी ताकत : भारतीय सेना की जमीनी ताकत कनाडा की तुलना में काफी ज्यादा है। हमारी थलसेना के पास 4,614 टैंक, 100,882 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 100 स्व-चालित तोपखाने, 3,311 ट्यूब तोपखाने और 1500 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (रॉकेट तोपखाने) हैं। कनाडा की थल सेना हमारी जमीनी ताकत में भी कहीं नहीं टिकती। इसके पास बख्तरबंद लड़ाकू वाहन का स्टॉक 31,852 है। वहीं कनाडाई थलसेना के पास महज 82 टैंकों की ही ताकत है।

समुद्री ताकत : भारत की समुन्द्र वाली ताकत भी कनाडा से कई गुना ज्यादा है। हमारी नौसेना बेड़े की कुल ताकत 295 है। हमारे पास 138 गश्ती जहाज, 19 छोटे जहाज, 18 पनडुब्बियां, 12 युद्ध पोत, 11 विध्वंसक और दो विमान वाहक हैं। वहीं कनाडाई नौसेना बेड़े की कुल ताकत 61 है। इसके पास 12 युद्ध पोत, 12 गश्ती जहाज और चार पनडुब्बियां ही हैं।

त्योहार और शादियों का बाजार भी अर्थव्यवस्था को करता है मजबूत

भारतीय शादियों व त्योहारों में होने वाले भारी व्यय से बाजार का विकास होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त बनती है।

भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार, पवित्र शादियों में विभिन्न आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांसारिक संस्कार संपन्न कराने के लिए समाज के गणमान्य नागरिकों, रिश्तेदारों व परिजनों को साथ लेकर विभिन्न प्रकार के भव्य आयोजन संपन्न किए जाते हैं। इन आयोजनों में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं एवं आजकल तो ऐसे शुभ अवसरों पर किए जा रहे भारी व्यय से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता दिखाई दे रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार, देश में बीते नवंबर से लेकर आगामी लगभग चार माह के दौरान 38 लाख से अधिक शादियों के आयोजन होने जा रहे हैं। इन चार माह में लगभग 4.75 लाख करोड़ की राशि व्यय होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 35 लाख शादियों पर 3.75 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई थी। शादी के विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च के अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष नए कपड़े और नए आभूषण खरीदने की मद पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होने वाली है।

इसके अलावा, मेहमानों की खातिरदारी पर 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होने जा रही है और शादी समारोह से जुड़े कार्यक्रमों पर भी इतनी ही राशि खर्च होने जा रही है। विश्व का कोई भी देश शादियों के मौसम में इतनी भारी-भरकम राशि खर्च नहीं करता। आज तो बगैर विवाह के 'लिव इन रिलेशन' नामक रिवाज ही चल पड़ा है। विकसित देशों के युवा इस प्रकार के रिवाजों के चलते बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं और कुछ समय पश्चात ही आपस में रिश्तों को 'तलाक' का रूप दे देते हैं। यदि इस बीच किसी जोड़े को बच्चा हो भी जाता है, तो उसे 'सिंगल पेरेंट' के रिवाज के तहत केवल मां के पास ही रहना होता है। इन्हीं कारणों के चलते आज विश्व के कई देशों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। कुल मिलाकर देखें, तो यह सनातन संस्कृति के संस्कार ही हैं, जो भारत में आज भी कुटुंब व्यवस्था को जीवित रखे हुए हैं। अन्यथा, विकसित देशों में चूंकि संयुक्त परिवार का चलन नहीं के बराबर है अतः बुजुर्गों की देखभाल इन देशों की सरकार को 'सामाजिक लाभ' योजना के अंतर्गत करनी होती है, जिस पर होने वाला खर्च इतना अधिक हो गया है कि इन देशों की बजट व्यवस्था ही भारी दबाव में आ गई है। इसके ठीक विपरीत, भारत में विभिन्न त्योहार भी बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं। इसके चलते इस वर्ष दीपावली एवं धनतेरस के त्योहारी मौसम में देश में 3.75 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। केवल करवाचौथ के दिन 15,000 करोड़ रुपये का व्यापार संपन्न हुआ था।

देश में त्योहारी मौसम में बीते अक्तूबर में 23 लाख वाहनों की बिक्री हुई है। चार लाख चारपहिया वाहनों एवं 19 लाख दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। आने वाले शादियों के मौसम में भी वाहनों की जबरदस्त बिक्री होने की संभावना है। इन वजहों से भारत में तेजी से गरीबी एवं बेरोजगारी भी कम हो रही है।

आज भारत में उच्च निवल संपत्ति वाले नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अतः समस्त मेहमानों सहित अब विदेश में जाकर शादी की रस्में संपन्न करने का प्रचलन भारत में बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से, अपने प्रधानमंत्री को देश के नागरिकों से विदेश में जाकर शादी की रस्में पूर्ण नहीं करने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि इससे शादी की रस्मों पर होने वाले व्यय का लाभ उस देश को मिल जाता है, जबकि भारत में ही पर्याप्त मात्रा में पर्यटन स्थल उपलब्ध हैं, जहां आसानी से शादियां विधि-विधान से संपन्न कर विवाह समारोह भी आयोजित किए जा सकते हैं। इससे शादी पर होने वाले खर्च का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा और देश का पैसा भी देश में ही बना रहेगा। आज भारतीय नागरिकों द्वारा सनातन संस्कृति के संस्कारों के पालन की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संघ ने वर्ष 2024 के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.3 फीसदी कर दिया है।

500 साल पुराना मंदिर जहां मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की है इजाज़त

इस मंदिर समिति द्वारा धार्मिक आयोजनों के आयोजन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर होने के बावजूद, मुसलमानों को परिसर के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति है।

ऐसे युग में जहां सांप्रदायिक वैमनस्य व्याप्त है और धर्म के बारे में सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर है, मध्य प्रदेश में 500 साल पुराने मंदिर की कहानी समाजिक एकता का बड़ा संदेश दे रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को गंगा जमुना तहजीब का शहर भी कहा जाता है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को समाहित करते हुए एक-दूसरे के साथ मिलकर त्योहार और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये आयोजन बुरहानपुर जिले के इच्छापुर में इच्छा देवी माता मंदिर परिसर में आयोजित किए जाते हैं।

इस मंदिर समिति द्वारा धार्मिक आयोजनों के आयोजन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर होने के बावजूद, मुसलमानों को परिसर के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति है। माना जा रहा है कि यह ऐसा करना वाला दुनिया का एकमात्र मंदिर हो सकता है। मंदिर समिति के विजय भागवत पवार ने कहा कि इच्छा देवी माता मंदिर दिवाली और ईद दोनों को समान धूमधाम और उत्सव की भावना के साथ मनाता है और सभी धार्मिक समुदायों के लोग यहां पूजा के लिए आते हैं। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है। किंवदंती के अनुसार, एक मराठा गवर्नर ने देवी इच्छा देवी के लिए एक कुआं और एक मंदिर बनाने की कसम खाई थी, अगर उसकी पत्नी से उसे बेटा पैदा होता। मंदिर को इच्छाएं पूरी करने वाली देवी भी कहा जाता है। उनकी इच्छा पूरी होने के बाद, उन्होंने एक मंदिर और एक कुआँ बनवाया। चैत्र मास में वहां एक वार्षिक मेला लगता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। मंदिर समिति धर्मार्थ के साथ-साथ परोपकारी कार्यों में भी शामिल है। पवार के मुताबिक, समिति ने इच्छापुर और बुरहानपुर के आसपास विकास कार्य किये हैं. सभी धार्मिक समुदायों के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलकर, इच्छा देवी माता मंदिर धार्मिक सद्भाव और भाईचारे के लिए एक उदाहरण और प्रतीक बन गया है।

पहले भरो शुल्क... फिर मिलेगी बिजली... इंदौर-उज्जैन संभाग में प्री पेड की तैयारी

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर-उज्जैन संभाग में प्री-पेड बिजली व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत सरकारी कार्यालयों से होगी। ये विभाग अपने-अपने कार्यालयों में खर्च होने वाली बिजली का अनुमानित अग्रिम भुगतान करेंगे और उसके बाद बिजली का उपयोग करेंगे। जितनी राशि जमा होगी, उतनी बिजली का ही उपयोग यहां हो सकेगा। इसके बाद फिर राशि जमा कर आपूर्ति को निर्बाध रखा जा सकेगा। प्रमुख सचिव के निर्देश पर कंपनी ने योजना तैयार कर ली है। हालांकि, इसे लागू करने से पहले कंपनी को नियामक आयोग की मंजूरी का इंतजार है। ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने स्मार्ट मीटर को लेकर बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि शासकीय कार्यालयों में अगले तीन महीनों में प्री-पेड बिल सिस्टम लागू करने की तैयारी हो। स्मार्ट मीटर योजना का लाभ भी कंपनी और उपभोक्ता को मिले।

सीधे कंट्रोल रूम पहुंचती है मीटर की रीडिंग

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सबसे पहले इंदौर से स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू किया था। अगले दो वर्षों में सभी शहर स्मार्ट मीटर से लैस करने की तैयारी में कंपनी जुटी है। स्मार्ट मीटर में सुविधा है कि रीडिंग सीधे बिजली कंपनी के कंट्रोल रूम जाती है। कनेक्शन काटने और शुरू करने की प्रक्रिया भी कंट्रोल रूम से कंप्यूटर के जरिए हो सकती है। लिहाजा स्मार्ट मीटर से यह सुविधा मिल सकती है कि इसे प्रीपेड के लिए प्रोग्राम किया जा सके। तय यूनिट खर्च होने पर आपूर्ति रुक जाए।

बिल पर मिलेगी छूट

सूत्रों के अनुसार, प्री-पेड विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को प्रत्येक यूनिट बिजली पर एक पैसे से 10 पैसे तक की छूट देने की योजना है। बिजली कंपनी उम्मीद कर रही है कि जल्द नियामक आयोग टैरिफ प्लान को मंजूरी दे देगा।

क्या पहले पैसा देंगे

बिजली कंपनी की इस योजना के पहले सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सरकारी विभाग अग्रिम बिल भुगतान करेंगे? दरअसल, बीते वर्षों में नगर निगम से लेकर पुलिस थानों और सरकारी विभागों का रवैया बिल चुकाने के प्रति सुस्त रहा है। निगम पर तो करोड़ों रुपये बकाया थे। बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री इंदौर के मनोज शर्मा के अनुसार, बीते महीनों में निगम का बकाया हम क्लियर करवा चुके हैं। ज्यादातर विभाग नियमित बिल चुका रहे हैं।

चुनाव की दहलीज पर खड़े पाक को चाहिए नौजवान लीडर...

पाकिस्तान में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि 70 साल बाद अब वक्त आ गया है कि युवा आगे आकर बुजुर्ग पीढ़ी की जगह लें, क्योंकि वे उस मुल्क की चुनौतियों का समाधान ढूंढने में नाकाम रहे हैं, जहां की विशाल युवा आबादी की परेशानियां उनसे अलग हैं, जिनका सामना उनके पूर्वजों ने किया था।

इस वक्त भारत और पाकिस्तान, दोनों ही चुनावी मोड में हैं और आने वाले महीनों में भी यही हालात रहने वाले हैं। मैं इस विषय पर लिखने के बारे में सोच ही रही थी, कि मेरे दिमाग में एक सवाल कौंधा, और मेरी हंसी छूट गई कि ज्यादातर नेता अशिक्षित क्यों होते हैं और क्या इस स्थिति में बदलाव आने की कोई संभावना है? दुनिया भर में लोग ऐसे राजनेताओं से आजिज आ चुके हैं। हालांकि ज्यादातर पश्चिमी राजनेता शिक्षित हैं, और हमारे यहां भी युवा नेता शिक्षित हैं। हैरत की बात है कि अफगानिस्तान के भीतर तालिबान, जिनकी कई पीढ़ियां दशकों से अमेरिका से लड़ रही हैं, की पढ़ाई अमेरिका में हुई है और उनका बोलने का लहजा अब भी अमेरिकी है।

मगर मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं के जिस पहलू की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, वह है उनकी उम्र। मैंने पहली बार भारतीय राजनेताओं पर तब ध्यान देना शुरू किया, जब मैं आउटलुक इंडिया के लिए लिख रही थी, जिसके संपादक विनोद मेहता थे। मुझे तभी महसूस हुआ कि पाकिस्तान की तुलना में भारतीय राजनेता काफी उम्रदराज थे। उस वक्त के ज्यादातर भारतीय नेता सत्तर या अस्सी वर्ष के ही थे। उनमें से कुछ बेहतरीन शख्सियत वाले राजनेताओं से मैं मिली भी। मुझे उन बुजुर्ग नेताओं से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन विभाजन के बाद दो नए देशों के तौर पर, जो नए संस्थानों के साथ नई राजनीति शुरू कर रहे थे, पाकिस्तान में राजनेता अपेक्षाकृत युवा थे। संसद जैसे लोकतंत्र के ज्यादातर प्रतीक पाकिस्तान को भारत से विरासत में मिले थे। पाकिस्तान के पास वैसे भी लोकतांत्रिक संस्थान कम ही रहे।

पाकिस्तान में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि 70 साल बाद अब वक्त आ गया है कि युवा पीढ़ी बुजुर्ग पीढ़ी की जगह ले, क्योंकि वे उस मुल्क की चुनौतियों का समाधान ढूंढने में नाकाम रहे हैं, जहां की विशाल युवा आबादी की परेशानियां उनसे अलग हैं, जिनका सामना उनके पूर्वजों ने किया था। इस संदर्भ में पहली आवाज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने उठाई, जिन्होंने एक चुनावी रैली में इमरान खान, अपने पिता आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और अन्य बुजुर्ग नेताओं को नेतृत्व छोड़ने और युवा पीढ़ी को नेतृत्व करने के लिए मौका देने के लिए कहा। बिलावल की टिप्पणियों से पीपीपी के अंदर और बाहर तो खलबली मच ही गई, उनके पिता आसिफ अली जरदारी भी न केवल नाराज थे, बल्कि इस बात से भी काफी आहत दिखे कि उनके बेटे ने अपने बयानों से वरिष्ठ राजनेताओं को नाराज कर दिया है। लेकिन जरदारी की प्रतिक्रिया राजनीतिक ज्यादा थी, क्योंकि चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और पार्टी गठबंधन

एवं सीटों के समायोजन की संभावना है।

जरदारी यह भूल गए कि पिछली सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए बिलावल एक मुद्दे पर अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए थे और अध्यक्ष से कहा था कि अब समय आ गया है कि पुराने राजनेताओं को पीछे हट जाना चाहिए और उन्हें तथा पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) की युवा नेत्री मरियम नवाज जैसे नेताओं को पार्टी का नेतृत्व करने देना चाहिए। उस वक्त जरदारी बिलावल की बगल में बैठकर सुनते रहे और चुप रहे थे। निचले सदन में बैठे पीपीपी सांसदों की ओर से कोई मेज नहीं थपथपाई गई। जैसा कि कहा जाता है- 'रात गई, बात गई' और जल्द ही बिलावल की टिप्पणी भुला दी गई। लेकिन इस बार जरदारी ने जोरदार मुखालफत करते हुए एक टीवी इंटरव्यू में कहा, 'बिलावल, अभी बच्चा है। वह राजनीति में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है और उसे गति पकड़ने में समय लगेगा। हम उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं।' लेकिन जरदारी ने यह भी कहा कि बिलावल ज्यादा प्रतिभाशाली व शिक्षित हैं और मुझसे बेहतर बोलते हैं, लेकिन 'अनुभव तो अनुभव है'। जैसे ही जरदारी ने सार्वजनिक रूप से अपने उस बेटे के खिलाफ बोला, जो एक सम्मानित और बेहद सक्षम व लोकप्रिय विदेश मंत्री के रूप में लंबा समय बिता चुका है, अचानक राजनीतिक आतिशबाजी शुरू हो गई और जरदारी की टिप्पणी देश भर में सुर्खियां बन गई। जरदारी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

अचानक कराची स्थित बिलावल हाउस से यह खबर आई कि बिलावल अचानक दुबई स्थित घर में रहने चले गए हैं। दरअसल, दुबई स्थित घर विशाल महल है, जो बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शेखों ने उपहार में दिया था, जब वह कई वर्षों के आत्म-निर्वासन के दौरान दुबई रहने चली गई थीं। यहां तक कि उनके निधन के बाद भी यूएई नेतृत्व ने परिवार से वह घर खाली करने के लिए नहीं कहा और जरदारी परिवार द्वारा इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत और पार्टी वगैरह के लिए किया जाता है। जरदारी के इंटरव्यू के तुरंत बाद बिलावल ने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्वीटर) की डीपी में अपनी तस्वीर बदल दी। उन्होंने अपनी एक बहुत पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जब वह बहुत छोटे थे। तस्वीर में वह सोफे पर बैठे हुए हैं और अपनी मां बेनजीर भुट्टो को देख रहे हैं, जो झुककर उन्हें देखकर मुस्करा रही हैं। जरदारी और बिलावल, दोनों को बेहतर जानने वाले एक विश्लेषक ने कहा कि इसके जरिये बिलावल ने अपने पिता को जो संदेश दिया है, वह यह कि 'मैं बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं।'

अगले ही दिन जरदारी भी पाकिस्तान से दुबई पहुंच गए और इस बात को लेकर काफी सवाल उठे कि पिता और पुत्र के बीच आखिर क्या हुआ। मीडिया की भारी दिलचस्पी को देखते हुए जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो ने तुरंत एक पारिवारिक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें बिलावल और जरदारी एक साथ खड़े हैं। लेकिन उस तस्वीर में जरदारी की छोटी बेटी असीफा भुट्टो नहीं हैं, जो अपने भाई के बहुत ही करीब है और पूरी तरह से बेनजीर भुट्टो जैसी दिखती हैं। पीपीपी की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया है कि वह पारिवारिक तस्वीर से क्यों गायब थीं।

दो माह बाद 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा कमजोर विद्यार्थियों की करा रहे विशेष तैयारी

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा पांच फरवरी से शुरू हो रही है। बोर्ड के विद्यार्थियों के पास मात्र दो माह का समय शेष है। ऐसे में चुनाव के कारण अब तक कुछ स्कूलों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, हालांकि छह दिसंबर से नौवीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा भी होगी। ऐसे में सौ प्रतिशत परिणाम लाने वाले स्कूलों ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। कुछ स्कूलों में त्योहार की छुट्टी और रविवार को भी कक्षाएं लगाकर तैयारी कराई जा रही है। साथ ही कुछ स्कूलों में कमजोर व प्रतिभावान विद्यार्थियों की सूची तैयार कर तैयारी करवाई जा रही है। कुछ स्कूलों ने आनलाइन के साथ-साथ अतिरिक्त कक्षाएं भी शुरू कर दिए हैं।

उत्कृष्ट विद्यालय में कमजोर व प्रतिभावान विद्यार्थियों का अलग-अलग ग्रुप बनाया गया है। इसमें प्रतिभावान विद्यार्थियों की शाम को आनलाइन कक्षाएं लगाई जा रही है। इसमें शिक्षक शाम सात से आठ बजे तक विद्यार्थियों के डाउट्स क्लीयर करते हैं। वहीं कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्कूल में सुबह आठ से नौ बजे तक अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जा रही है।साथ ही छुट्टी के दिन सभी की कक्षाएं लगाई जा रही है। साप्ताहिक टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। इसमें एक-एक सवाल पर विद्यार्थियों को समझाया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल शासकीय उमावि बरखेड़ी भोपाल में अवकाश के दिनों में भी कक्षाएं लगाई जा रही है। इसमें तिमाही परीक्षा से कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनकी उपलब्धि स्तर में सुधार करना उनकी समझ को पहचान कर उन्हें सिखाने का प्रयास करना है। इस कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कराया जा रहा है। 28 नवंबर से स्कूल में छमाही परीक्षा को देखते हुए विशेष कक्षाएं लगाई जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति कम है उनकी काउंसलिंग की जा रही है। रेमेडियल कक्षा से अनुपस्थित रहने वाले कमजोर विद्यार्थियों की मानिटरिंग की जा रही है।कमजोर विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर सुधारने और उनकी स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के शिक्षकों को टीचर वार्डन बनाया गया है।

सीएम राइज स्कूल निशातपुरा में दशहरा व दीपावली से लेकर हर त्योहार और रविवार को भी कक्षाएं लगाई जा रही हैं।साथ ही हर दिन अतिरिक्त कक्षाएं लगाईं जा रही हैं। तिमाही परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक कक्षा शिक्षक को कमजोर विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि उन्हें अलग से पढ़ा सकें।इसके अलावा क्लास में हर महीने टेस्ट लेकर टापर को चिन्हित कर उसकी फोटो लगाई जाती है,ताकि अन्य विद्यार्थी प्रेरित हो सकें।

50 से अधिक स्कूलों की मान्यता लंबित होने पर स्वत: निरस्त मानी जाएगी...

प्रदेश के 50 से अधिक निजी स्कूलों की मान्यता अधर में लटक गई है। इन स्कूलों ने पोर्टल पर पूरी जानकारी अपडेट नहीं की है। सत्र 2023-24 की मान्यता प्रक्रिया में जिन स्कूलों द्वारा मान्यता के लिए आवेदन किया था। अगर उनकी मान्यता जारी न होकर किसी भी स्तर पर लंबित है तो उन स्कूलों की मान्यता आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में निर्देशित किया गया है कि कलेक्टर के समक्ष मान्यता के लिए लंबित प्रकरण वाले स्कूल 30 नवंबर तक विशेष विलंब शुल्क की राशि पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए अगले सत्र के लिए मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं शैक्षणिक सत्र 2024-25 के नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार पहली से आठवीं तक के निजी स्कूलों को नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण के आवेदन करने के बाद विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसीसी) को 15 दिन में भौतिक सत्यापन करना होगा। आरटीई के मान एवं मानकों की पूर्ति होने तथा निजी स्कूल भवन, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। यह रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक(डीपीसी) को भेजना होगी। अगले सत्र के लिए डीपीसी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण 20 नवंबर तक कर दिया गया है। अब स्कूल संचालकों को 20 दिसंबर तक मान्यता आवेदन निरस्ती के प्रकरण में कलेक्टर के समक्ष अपील करना होगी। जिसका निराकरण कलेक्टर द्वारा 30 दिन के भीतर किया जाएगा। इसके बाद आयुक्त एवं संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के समक्ष अपील का विकल्प स्कूल संचालक के पास रहेगा।

नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली संस्था के लिए मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला के लिए पांच हजार रुपये, माध्यमिक शाला के लिए 7500 रूपये और प्राथमिक सह माध्यमिक शाला के लिए 10 हजार रूपये निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा। मान्यता नवीनीकरण के लिए प्राथमिक शाला के लिए दो हजार रूपये, माध्यमिक शाला के लिए तीन हजार रूपये और प्राथमिक सह माध्यमिक शाला के लिए चार हजार रूपये प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि के लिए एकमुश्त जमा किया जाना होगा।

पाक के कलाकारों को भारत में बैन करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पाकिस्तान के कलाकारों को प्रतिबंधित करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत में दायर याचिका में अपील की गई थी कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में प्रदर्शन या काम करने की अनुमति न दी जाए। कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए अदालत ने फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने फैज अनवर कुरैशी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार फैज अनवर कुरैशी एक सिने कार्यकर्ता और कलाकार होने का दावा करते हैं। अदालत ने कुरैशी से कहा कि आपको इस अपील पर बार-बार जोर नहीं देना चाहिए। आपको इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की दलील देने से भी इनकार कर दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने की थी यह टिप्पणी

इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के कलाकारों को प्रतिबंधित करने की मांग खारिज कर दी थी। अदालत ने 'देशभक्ति' के इजहार पर भी अहम टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश से, विशेषकर पड़ोसी देश से आए लोगों या कलाकारों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की जरूरत नहीं है।

याचिका में किन लोगों पर प्रतिबंध की मांग

याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि किसी भी पाकिस्तानी कलाकार पर, भारतीय नागरिकों, कंपनियों, फर्मों और एसोसिएशनों में काम पर रखने, काम ऑफर करने, उनकी किसी भी सेवा को लेने या किसी भी एसोसिएशन में प्रवेश करने आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाए। जिन लोगों पर प्रतिबंध की मांग की गई है, इनमें सिने कर्मी, गायक, संगीतकार, गीतकार और तकनीशियन शामिल हैं।

देशभक्त होने के लिए दुश्मनी जरूरी नहीं

बंबई की अदालत ने याचिका खारिज कर अपनी टिप्पणी में कहा था कि सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम नहीं है। ये काफी पीछे की तरफ खींचने जैसी मांग है। याचिका में कोई योग्यता नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए, किसी को विदेश खासकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की जरूरत नहीं है।

क्रिकेट वर्ल्डकप में पाक के खेलने का जिक्र

बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश में कहा था कि कला, संगीत, खेल, संस्कृति, नृत्य आदि ऐसी गतिविधियां हैं जो राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और राष्ट्रों से ऊपर उठती हैं। वास्तव में इनसे देशों के बीच शांति, एकता और सद्भाव बढ़ता है। कोर्ट ने आगे कहा था कि भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप 2023 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हिस्सा ले रही है।

सर्दी-जुकाम व खांसी की छुट्टी कर देंगे ये पांच अमेजिंग जूस, स्वाद के साथ फिटनेस भी

सर्दियों में सोच-समझकर जूस का सेवन करना चाहिए। क्योंकि बिना समझे जूस आदि पीने से सर्दी-जुकाम हो सकता है। इसलिए सर्दियों में ऐसे फूड्स का जूस पीना चाहिए। जिनकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में हम सभी को अपनी डाइट का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। क्योंकि हेल्दी और प्रॉपर डाइट लेने से न सिर्फ हमारा शरीर वार्म रहता है। बल्कि शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ऐसे में कई लोग सर्दियों में जूस का सेवन भी करते हैं। लेकिन सर्दियों में सोच-समझकर जूस का सेवन करना चाहिए। क्योंकि बिना समझे जूस आदि पीने से सर्दी-जुकाम हो सकता है। इसलिए सर्दियों में ऐसे फूड्स का जूस पीना चाहिए। जिनकी तासीर गर्म होती है। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे जूस के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनको पीने से आप हेल्दी और फिट रहेंगे।

गाजर-अदरक जूस

गाजर और अदरक जूस में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। यह जूस हमारी त्वचा को जवां और ग्लोइंग बनाता है। यह जूस शरीर में कोलेजन बढ़ाने के साथ ही त्वचा की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अदरक के जूस में जिंजरोल पाया जाता है। जो कैंसर कोशिकाओं के विनाश को बढ़ावा देता है।

चुकंदर जूस

चुकंदर हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। ऐसे में आप सर्दियों में चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में चुकंदर के साथ अदरक डालकर इसका सेवन करने से शरीर को एंटीइंफ्लामेटरी, नाइट्रेट, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन व मिनरल्स मिलेगा। अगर आप रोजाना 500 मिलीलीटर बीटरूट जूस पीते हैं। तो इससे 15 फीसदी तक शरीर की थकावट कम हो सकती है।

क्रैनबेरी जूस

क्रैनबेरी जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। जो हमारी डायजेशन सिस्टम को ठीक करने के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। क्रैनबेरी जूस में विटामिन सी और ई भरपूर मात्रा पायी जाती है। इस जूस का सेवन करने से हमारे शरीर से टॉक्सिन पदार्थ निकल जाता है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में भी राहत देने का काम करता है। आप संतरा, मौसंबी और अंगूर को मिलाकर क्रैनबेरी जूस बना सकते हैं।

सिट्रस फ्रूट जूस

सिट्रस फ्रूट जूस विटामिन सी से भरपूर होता है। यह इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के साथ ही इंफेक्शन और कोल्ड फ्लू से बचाता है। सिट्रस फ्रूट जूस फ्लेवोनोइड्स दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साथ ही विटामिन सी के होने से यह त्वचा को ग्लोइंग बनाता है।

कीवी जूस

कीवी में कैरोटेनोइड्स, पॉलीपेनोल्स और डाइटरी फाइबर पाया जाता है। इसमें मौजूद तत्व कोल्ड और फ्लू से बचाने का काम करते हैं। साथ ही यह जूस झुर्रियों को कम करता है। जिससे हमारी त्वचा यूथफुल दिखती है।

एनीमिया होने पर दिखाई देते हैं ऐसे लक्षण...

डाइट में फौरन सुधार न करने से दिक्कत में पड़ सकते हैं आप

महिलाओं में एनीमिया की समस्या ज्यादा देखी जाती है। खासकर गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसे में इन चीजों का सेवन करने से शरीर में खून बढ़ता है। बता दें कि हीमोग्लोबिन या ब्लड टेस्ट के जरिए एनीमिया की जांच की जाती है। रक्त संबंधित रोग को एनीमिया कहा जाता है। इस बीमारी के चलते व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होने लगती है। वहीं हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। बता दें कि फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। पुरुष और महिला दोनों में यह बीमारी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं में यह समस्या देखी जाती है। खासकर गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर में खून की कमी हो जाती है। जिसके कारण प्रेग्नेंसी में महिलाओं को कमजोरी, थकान, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और चक्कर आदि आने लगते हैं। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को किन फूड्स का सेवन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

एनीमिया के लक्षण

एनीमिया के लक्षणों के दिखते ही सबसे पहले टेस्ट करवाएं। इससे पुष्टि हो जाएगी। वहीं प्रग्नेंसी के दौरान महिलाओं को एनीमिया की समस्या होती है। लेकिन कई बार महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं। जिसका असर गर्भ में पलने वाले बच्चे पर पड़ता है। कई मामलों में स्थिति इतनी अधिक गंभीर हो जाती है कि बच्चे की जान बचाना मुश्किल हो जाता रहै। ऐसे में अगर आपके परिवार में किसी की एनीमिया की मेडिकल हिस्ट्री है। तो डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बनाएं। हीमोग्लोबिन या ब्लड टेस्ट के जरिए एनीमिया की जांच की जाती है।

आयरन रचि फूड्स

एनीमिया के लक्षण नजर आने पर आयरन रिच फूड्स का सेवन करना चाहिए। बता दें कि पालक, काली मसूर दाल, लाल मसूर दाल और चना दाल में आयरन की अच्छी मात्रा पायी जाती है। वहीं दाल में आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में इन चीजों का सेवन करने से शरीर में खून बढ़ता है। वहीं इसके अलावा आप अंजीर, किशमिश, अखरोट और काजू आदि ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही अंडे का सेवन भी एनीमिया में फायदेमंद माना जाता है। कद्दू के बीज का सेवन एनीमिया में लाभकारी होता है।

फोलिक एसिड

एनीमिया के मरीजों को हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर फोलिक एसिड का सेवन भी करना चाहिए। बता दें कि फोलिक एसिड विटामिन बी का एक रूप है। फोलकि एसडि का सेवन ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए फायेदमंद माना जाता है। वहीं प्रेग्नेंसी के दौरान भी महिलाओं को फोलिक एसिड का सेवन किए जाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि यह गर्भ में पलने वाले बच्चे के विकास के लिए भी जरूरी माना जाता है। ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह पर विटामिन-B12 का सेवन कर सकती हैं।

डिलीवरी के बाद ये 5 फूड्स अपनी डाइट में करें शामिल, जल्द दूर होगी कमजोरी

डिलीवरी के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने की वजह से महिलाओं के शरीर में खून की कमी आ जाती है। ऐसे में इन इंडियन फूड्स का सेवन कर हेल्दी और फिट रह सकती हैं। ऐसे में हम आपको इन फूड्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

प्रेग्नेंसी से पहले और इस दौरान कई फूड्स ऐसे होते हैं, जिनसे सेवन से परहेज करने को कहा जाता है। वहीं प्रेग्नेंसी के बाद महिलाओं को कई तरह के हल्दी फूड्स का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इन फूड्स के सेवन से महिलाओं को जल्द रिकवरी करने में मदद मिलती हैं। क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं का शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे में आप इंडियन फूड्स का सेवन कर अपने शरीर का ध्यान रख सकती हैं। बता दें कि डिलीवरी के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने की वजह से महिलाओं के शरीर में खून की कमी आ जाती है। ऐसे में इन इंडियन फूड्स का सेवन कर हेल्दी और फिट रह सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इन फूड्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

मोरिंगा की पत्तियों का सेवन

महिलाओं को डिलीवरी के बाद मोरिंगा की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। मोरिंगा की पत्तियों में विटामिन ए, बी, सी के अलावा आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। इसके सेवन से शरीर की कमजोरी दूर होती है और शरीर को भी ताकत मिलती है। आप सब्जियों में मोरिंगा की पत्तियों को डालकर खा सकती हैं।

खाएं साबुत अंकुरित अनाज

महिलाओं को साबुत अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। अगर आ डिलीवरी के बाद अंकुरित अनाजों का सेवन करती हैं। तो इससे आपको ताकत मिलती है। साबुत अंकुरित अनाज में आप रागी, बाजरा, गेंहू और ज्वार

आदि को शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो आटे में इन्हें पिसवाकर भी इनका सेवन कर सकती हैं।

लौकी

डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी डाइट में लौकी को भी शामिल करना चाहिए। लौकी के सेवन से शरीर हाइड्रेट होने के साथ शरीर में दूध की मात्रा में भी वृद्धि होती है। बता दें कि लौकी में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फोलेट, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता हैं। जो वेट कम करने के साथ ही पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। आप लौकी का हलवा और सब्जी बनाकर भी इसे खा सकती हैं।

लहसुन

इसके साथ ही महिलाओं को अपनी डाइट में लहसुन भी शामिल करना चाहिए। लहसुन इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के साथ ही आपके शरीर को भी गर्म रखता है। वहीं इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। आप लहसुन को सब्जियों की करी और सूप आदि में शामिल कर सेवन कर सकते हैं।

मेथी के दाने

शरीर के लिए मेथी के दाने काफी फायदेमंद होते हैं। ऐसे में बच्चों को स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को मेथी के दाने का सेवन जरूर करना चाहिए। बता दें यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और दूध की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। मेथी के बीजों को अंकरित करके और मेथी के दानों को पंजीरी और लड्डू में मिलाकर भी खाया जा सकता है।

सर्दियों में मॉर्निंग वॉक के दौरान हॉर्ट पेशेंट न बरते कोई भी लापरवाही

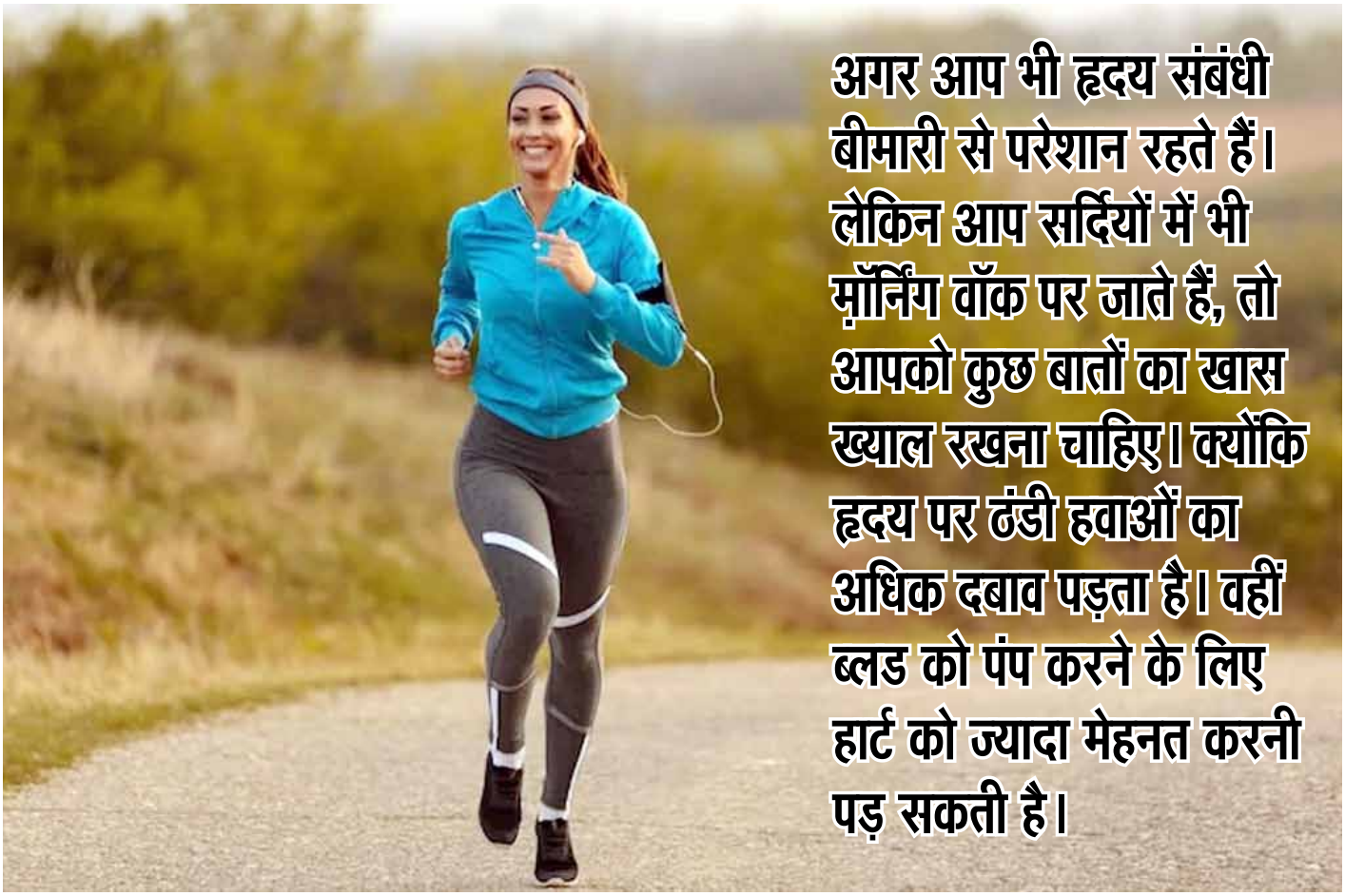

अगर आप भी हृदय संबंधी बीमारी से परेशान रहते हैं। लेकिन आप सर्दियों में भी मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हृदय पर ठंडी हवाओं का अधिक दबाव पड़ता है। वहीं ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।

सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी उठाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, वह सर्दी हो या गर्मी हमेशा मॉर्निंग वॉक कर खुद को फिट रखते हैं। लेकिन सर्दियों में मॉर्निंग वॉक के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं जो लोग हृदय रोगी हैं, उनको मॉर्निंग वॉक पर जाते समय अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। क्योंकि सर्दियों में हृदय रोगियों की दिक्कतें अधिक बढ़ सकती हैं। बता दें कि हृदय पर ठंडी हवाओं का अधिक दबाव पड़ता है। जिसकी वजह से ब्लड को पंप करने के लिए हृदय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे में अगर आप भी हृदय संबंधी बीमारी से परेशान रहते हैं, लेकिन आप सर्दियों में भी मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक के दौरान हृदय रोगियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

धूप निकलने के बाद करें वॉक

हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को जल्दी सुबह वॉक पर जाना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि सुबह के समय चलने वाली ठंडी हवाएं आपकी समस्या को बढ़ा सकती हैं। इसलिए जब थोड़ी धूप निकल आए, तब वॉक करें। इससे आपको अधिक ठंड भी नहीं लगेगी।

गर्म कपड़े पहनकर करें वॉक

हार्ट पेशेंट होने पर आप गर्म कपड़े पहनकर मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान अच्छे से गर्म कपड़े पहन लें। इससे आपको अधिक ठंड नहीं लगेगी और आप सर्द हवाओं से भी बचे रहेंगे। मॉर्निंग वॉक के दौरान सिर्फ टी-शर्ट या शर्ट में बाहर जाने से बचना चाहिए।

हल्की एक्सरसाइज जरूर करें

सर्दियों में खुद को फिट रखने के लिए अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो आप सुबह के समय हल्की एक्सरसाइज भी कर सकते है। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। साथ ही एक्सरसाइज करने से आपको गर्माहट के साथ फ्रेशनेस भी फील होगी। बता दें कि एक्सरसाइज हमारे हार्ट के लिए भी बेहतर होती हैं।

हेल्दी डाइट लेना है जरूरी

मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले थोड़ा-बहुत कुछ खाकर बाहर निकलें। सुबह मॉर्निंग वॉक पर खाली पेट जाने से बचना चाहिए। आप चाहें तो बाहर वॉक पर जाने से पहले ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ पानी का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

- रोजाना नियमित तौर पर बीपी की चांज करवानी चाहिए। हाई बीपी की स्थिति होने पर सुबह वॉक पर जाने से बचना चाहिए।
- सर्दियों में हार्ट पेशेंट को इनडोर एक्टिविटीज करनी चाहिए। इससे उनके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है।
- ठंड अधिक होने पर सुबह वॉक पर जाने से बचना चाहिए। क्योंकि यह हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है।
- अधिक तला-भुना और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए।
- धूम्रपान, शराब और कैफीन ज्यादा सेवन नहीं करें।

इस मंदिर में माता खुद करती हैं अग्नि स्नान, जानिए इसके पीछे का रहस्य

राजस्थानी के ईडाणा माता मंदिर में हर साल अपने आप आग लग जाती है। आग लगने पर मां ईडाना की मूर्ति को छोड़कर मंदिर में कुछ भी शेष नहीं बचता है। आइए जानते हैं ईडाणा माता मंदिर के कुछ रोचक बातों के बारे में।

भारत देश में कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों में आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं। जिनके आगे विज्ञान भी फेल है। ऐसा ही एक चमत्कारिक मंदिर राजस्थान में है। यह मंदिर राजस्थान का ईडाणा माता मंदिर है। बता दें कि हर साल इस मंदिर में अपने आप आग लग जाती है। आग लगने पर मां ईडाना की मूर्ति को छोड़कर मंदिर में कुछ भी शेष नहीं बचता है। कहा जाता है कि हर साल मां ईडाणा अग्नि स्नान करती हैं। यह मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर से 60 किमी दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है।

देवी के अग्नि स्नान का महत्व : ईडाणा माता मंदिर में कभी भी आग लग जाती है। मान्यता के अनुसार, अग्नि स्नान के दौरान माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है। ऐसे में मंदिर के अंदर मौजूद भक्तों का चढ़ाया प्रसाद, मां की चूनर आदि सब जलकर राख हो जाता है। अग्नि स्नान के दौरान सिर्फ मां की मूर्ति बचती है। बताया जाता है कि मां की अग्नि स्नान के बाद मंदिर की आग खुद से बुझ जाती है। अग्नि स्नान को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग जाती है। हांलाकि यह आग कैसे लगती है, इसके बारे में आजतक कोई जानकारी नहीं मिली है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मां को अग्नि स्नान करते देखता है, वह खुद को धन्य समझता है।

रोजाना द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत का पाठ करने से मिलती है महादेव की कृपा

अगर आप भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। तो आप घर पर भी रोजाना द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्त्रोतम का पाठ कर सकते हैं। इसका पाठ करने से व्यक्ति पर 12 ज्योतिर्लिंग की कृपा बनी रहती है। देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। मान्यता के मुताबिक जो भी व्यक्ति इनके दर्शन करता है। उसे पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में आप रोजाना द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्त्रोतम का पाठ कर सकते हैं।

द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् ।
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥
श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् ।
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् ॥
अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् ।
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् ॥
कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय ।
सदैवमान्धातृपुरे वसन्तमोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ॥
पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम् ।
सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि ॥
याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः ।
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ॥
महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः ।
सुरासुरैर्यक्ष महोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे ॥
सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे ।
यद्दर्शनात्पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे ॥
सुताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यैः ।
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥
यं डाकिनिशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च ।
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि ॥
सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दम् ।
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥
इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम् ।
वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणम् प्रपद्ये ॥
ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण ।
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ॥

भारत ही नहीं विदेशों में भी हैं भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान...

भगवान के प्राचीन उपस्थिति के भौतिक निशान पृथ्वी पर साफ देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर हनुमान जी के विशाल पैरों के निशान पाए गए हैं। आज हम आपको उन जगहों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

हिंदू धर्म में कई देवी-देवताओं की पूजा की जाती है। इन्हीं देवताओं में हनुमान जी हैं। जिन्हें भगवान श्रीराम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। वहीं धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए भगवान ने कई बार धरती पर जन्म लिया है। भगवान के प्राचीन उपस्थिति के भौतिक निशान पृथ्वी पर साफ देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर हनुमान जी के विशाल पैरों के निशान पाए गए हैं।

ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जहां पर भगवान हनुमान के बड़े विशाल पैरों के निशान जमीन पर बने हुए हैं। मान्यता के अनुसार, इनमें से कुछ पदचिन्ह सैकड़ों-लाखों वर्ष पुराने हैं। रामायण में वर्णित भगवान राम और भगवान हनुमान के संबंध से सभी परिचित हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि धरती पर आज भी भगवान हमारे बीच हैं। तो आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में...

हनुमानजी के पदचिह्न

श्रीलंका में पाए जाने वाले विशाल पैरों के निशान को भगवान हनुमान के पदचिन्ह माने जाते हैं। बताया जाता है कि जब भारत से श्रीलंका की ओर हनुमान चले, तो वह इसी स्थान पर उतरे थे। भगवान हनुमान के शरीर की शक्ति इतनी अधिक थी कि इस ठोस पत्थर में उनके पदचिन्ह दब गए।

पेनांग में पदचिन्ह

आपको बता दें कि मलेशिया के पेनांग में भी हनुमान जी के विशाल पदचिन्हों को देखा जा सकता है। भगवान के इन पदचिन्हों के दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए श्रद्धालु हनुमान जी के पदचिन्ह पर सिक्के फेंकते हैं।

थाइलैंड में पदचिन्ह

इसके अलावा थाइलैंड में भी विशाल पदचिन्ह पाए जाते हैं। हांलाकि यह पदचिन्ह किसके हैं। इसके बारे में साफ जानकारी नहीं है। ऐसे में विशाल पैरों के निशान आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में भी मिलते हैं। यहां के लोगों का मानना है कि यह भगवान हनुमान के पदचिन्ह हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है यह पदचिन्ह माता सीता के हैं। आप भारतीय महाकाव्य रामायण में भी लेपाक्षी के ऐतिहासिक शहर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर ले जा रहा था। तब जटायू और रावण का युद्ध हुआ था। उस दौरान धरती पर मां सीता के पदचिन्ह बने थे। वहीं जटायु वृद्ध होने के कारण अधिक समय तक रावण से युद्ध नहीं कर पाया। रामायण के मुताबिक जटायु अपने अंतिम समय में भगवान श्रीराम और भ्राता लक्ष्मण से इसी स्थान पर मिला था।

...आखिर गुजरात स्थित भगवान शिव के ज्योर्तिलिंग का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा?

शापमुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वतीजी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारर्थ यहां निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहां रहने लगे।

भगवान श्री सोमनाथ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्रीकृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में भी मिलती है। पुराणों में उल्लिखित पहली कथा के मुताबिक दक्ष प्रजापति की सत्ताइस कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था। किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनमें एक केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट होता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनायी। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्र देव को बहुत प्रकार से समझाया। किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें 'क्षयी' हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गये। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा-शीतलता-वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गयी। चंद्रमा भी बहुत दुःखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इन्द्र आदि देवता तथा वसिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्माजी के पास गये। सारी बातों को सुनकर ब्रह्माजी ने कहा- चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिये अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जायेगा और ये रोगमुक्त हो जाएंगे।

उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए दस करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय- भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा- चंद्रदेव! तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जायेगी। कृष्णपक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक-एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक-एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्माजी के इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दसों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्व की भांति करने लगे।

शापमुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वतीजी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारर्थ यहां निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहां रहने लगे।

पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा स्कन्द पुराण आदि में विस्तार से बतायी गयी है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ मानकर यहां तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पालक और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिये सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक-पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव, अनायास सफल हो जाते हैं।

सर्दियों में पाएं गुलाबी निखार... लगाएं टमाटर के ये फेस पैक

निखरी-निखरी होगी त्वचा

सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाएं हमारी त्वचा को ड्राई बनाती हैं और स्किन के ग्लो को कम करती है। ऐसे में आप सर्दी के मौसम में नेचुरल तरीके से अपनी स्किन केयर कर सकती हैं, इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। सर्दियों में हमें न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि त्वचा का भी खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाएं हमारी त्वचा को ड्राई बनाती हैं और स्किन के ग्लो को कम करती है। जिसके चलते सर्दियों में स्किन का कलर थोड़ी डार्क हो जाती है। हांलाकि सर्दियों में स्किन की देखभाल करने के लिए लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह महंगे प्रोडक्ट होने के बाद भी कई बार हमें मनमुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है।

ऐसे में अगर आप भी सर्दियों में अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से सर्दियों में टमाटर का फेस पैक आपकी स्किन के लिए फायदेमंद साबित होगा। टमाटर में लाइकोपिन और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है, जो आपकी त्वचा को पोषण देने के साथ ही रंगत साफ करता है। वहीं यह फेस पैक ड्राई स्किन की समस्या को दूर करने से साथ सर्कुलेशन को बढ़ाता है।

टमाटर और हल्दी का फेसपैक
कद्दूकस किया हुआ टमाटर- 2 चम्मच
हल्दी- 1/4 चम्मच

टमाटर और हल्दी का फेसपैक बनाने के लिए 1 मीडियम साइज का टमाटर लें। टमाटर को कद्दूकस कर इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर फेस और गर्दन पर अप्लाई करें। फिर इस फेसपैक को 20 मिनट तक लगाए रहें और समय पूरा होने के बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। यह फेसपैक रंगत निखारने के साथ ही पिंपल्स की समस्या हो भी कम करने में मददगार है। साथ ही इससे आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहती है।

टमाटर और शहद के फेसपैक की सामग्री
टमाटर का रस- 3 चम्मच
शहद- 1 चम्मच

इस फेसपैक को बनाने के लिए सबसे पहले एक टमाटर का रस निकाल लें। फिर टमाटर के रस में शहद को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को 15 मिनट के लिए फेस पर अप्लाई करें। टाइम पूरा होने के बाद फेस को पानी से धो लें। इस फेसपैक से आपकी त्वचा को पोषण मिलता है और स्किन चमकदार बनती है। यह आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है।

टमाटर और दही के फेस पैक की सामग्री
टमाटर का रस- 3 चम्मच
दही- 1 चम्मच

इस फेसपैक को बनाने के लिए 3 चम्मच टमाटर के रस में दही मिला लें। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से फेंट लें। अब इस फेसपैक को 15 मिनट के लिए चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें। फिर नॉर्मल पानी से चेहरे को धो लें। टमाटर और दही से बना यह फेसपैक आपकी त्वचा को पोषण देने के साथ ड्राई स्किन की समस्या को दूर करता है। साथ ही यह आपकी त्वचा को सॉफ्ट बनाता है। हांलाकि इन फेसपैक को चेहरे पर अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।

जानिए क्या होते हैं ओलंपिक खेल..?

पूरी दुनिया में ओलंपिक खेल मुख्यत चार प्रकार के होते हैं। इनमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक खेल शामिल है। इसे खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं।

ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 से ओलंपिक की शुरुआत हुई। उसी दौरान ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। पूरी दुनिया में ओलंपिक खेल मुख्यत चार प्रकार के होते हैं। इनमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक खेल शामिल है। इसे खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं।

इसके अलावा ओलंपिक खेल में तीन तरह के मेडल खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल होते हैं। इसके अलावा ओलंपिक के झंडे में 5 रिंक, नीले, डार्क पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। जो पांच महाद्वीप अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया के आपस में जुड़े होने का प्रतीक हैं। इसे 1913 में पियरे डि कोबर्टिन ने डिजाइन किया था।

ओलंपिक खेल क्या है?

दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता को ओलंपिक खेल कहते हैं। जिसमें दुनियाभर के बेहतरीन एथलीट भाग लेते हैं और अपने-अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक खेल हर चार साल में आयोजित होते हैं। ओलंपिक खेलों की इस समयावधि को ओलंपियाड कहते हैं। ओलंपिक खेलों की देखरेख IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। जानकारी के मुताबिक ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। तब से ये खेल हर चार साल में आयोजित होते हैं। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 में इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ था।

ओलंपिक खेलों का उद्देश्य

पियरे डे कोबर्टिन को ओलंपिक का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को किया था। इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड के लॉजेन में है। बता दें कि, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रत्रा है। साथ ही खेलों के माध्यम से विश्व शांति बनाए रखना है। इसके साथ ही विश्व को एकजुट रखना है। ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है।

चार तरह के होते हैं ओलंपिक

ओलंपिक खेल तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक शामिल हैं। इन सभी ओलंपिक खेलों की अलग-अलग खासियत होती है।

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारत ने की टीम की घोषणा

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन और चार फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाले डेविस कप विश्व ग्रुप एक प्ले ऑफ मुकाबले के लिए शनिवार को छह सदस्यीय टीम घोषित की। रामकुमार रामनाथन, एन श्रीराम बालाजी, युकी भांबरी, निकी कालियांदा पूनाचा, साकेत माइनेनी और दिग्विजय प्रताप सिंह को टीम में शामिल किया गया है। दिग्विजय प्रताप सिंह रिजर्व खिलाड़ी हैं। रामनाथन और पूनाचा एकल मैच खेल सकते हैं जबकि युकी, बालाजी और माइनेनी में से किन्हीं दो को युगल मैच के लिए चुना जा सकता है। रोहित राजपाल टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान होंगे जबकि जीशान अली कोच की भूमिका निभाएंगे। अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) ने विज्ञप्ति में बताया कि चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता नंदन बल ने की तथा समिति के अन्य सदस्य बलराम सिंह, मुस्तफा घोष, साई जयलक्ष्मी, राजपाल, जीशान और सचिव अनिल धूपर भी इसमें उपस्थित थे। भारत ने इससे पहले आखिरी बार 1964 में पाकिस्तान का दौरा किया था और तब उसने 4-0 से जीत दर्ज की थी। भारत अभी तक पाकिस्तान से कभी नहीं हारा है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ सभी आठ मुकाबले जीते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी मुकाबला 2019 में तटस्थ स्थल पर खेला गया था। भारत ने इस मुकाबले में भी 4-0 से जीत हासिल की थी।

किंग का कॉमेडी अवतार दिखा..

मशहूर कहानीकार और निर्देशक राजकुमार हिरानी द्वारा तैयार की गई इस फिल्म में बेहद चहेते शाहरुख खान ने अभिनय किया है, जो तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्की कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर जैसे शानदार कलाकारों की टोली का हिस्सा होंगे।

द डंकी: ड्रॉप 4 (The Dunki: Drop 4) साल की बहुप्रतीक्षित फिल्म है। अब उसकी एक झलक पेश हो चुकी है। मास्टर कहानीकार और निर्देशक, राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित, इस फिल्म में प्रिय शाहरुख खान के साथ-साथ तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्की कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर जैसे शानदार कलाकार शामिल हैं। ड्रॉप 4, दर्शकों को साल की सबसे दिल छू लेने वाली फिल्म की बहुप्रतीक्षित झलक देती है। मशहूर कहानीकार और निर्देशक राजकुमार हिरानी द्वारा तैयार की गई इस फिल्म में बेहद चहेते शाहरुख खान ने अभिनय किया है, जो तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्की कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर जैसे शानदार कलाकारों की टोली का हिस्सा होंगे। ट्रेलर रेसिंग ट्रैक पर दौड़ रहे हार्डी के पुराने संस्करण के एक असेंबल के साथ समाप्त होता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे उन्होंने शुरू किया था और वही इसे ख़त्म भी करेंगे। हमें यह देखने के लिए 21 दिसंबर तक इंतजार करना होगा कि हार्डी अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं। यह वीडियो राजकुमार हिरानी की प्यारी दुनिया की एक झलक पेश करता है। ट्रेन में शाहरुख के साथ शुरुआत, आगे आने वाले रोमांच के लिए माहौल तैयार करती है। वीडियो यूनिट में शाहरुख द्वारा निभाए गए हार्डी से शुरू होने वाले अद्भुत सनकी पात्रों का परिचय दिया गया है, जो पंजाब के एक सुरम्य गांव में प्रवेश करता है और उत्साही दोस्तों के एक समूह - मनु, सुखी, बुग्गू और बल्ली का सामना करता है, जो सभी लंदन की यात्रा करने का एक आम सपना साझा करते हैं।

हाल ही में आस्क एसआरके सत्र के दौरान, अभिनेता से पूछा गया कि वह पूरी अवधारणा के बारे में कितना जानते हैं और किस चीज़ ने उन्हें इस परियोजना को चुनने के लिए आकर्षित किया। शाहरुख ने कहा, उन्हें इसके बारे में शायद ही कुछ पता था, उन्होंने कहा, 'वास्तव में शायद ही कुछ। राजू और अभिजात ने इसे मेरी जानकारी में लाया। इसके बारे में जानना और इसके कुछ हिस्सों को चित्रित करना आकर्षक...खतरनाक और काफी जबरदस्त अनुभव है।

फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'ये कहानी मैंने शुरू की थी, लालतू से! इसे खत्म भी मैं ही करूंगा... अपने उल्लू दे पत्थरों के साथ। डंकी का ट्रेलर आपको एक ऐसा सफर दिखाएगा जो राजू सर के दृष्टिकोण के साथ शुरू हुआ। यह आपको दोस्ती की एक पागलपन भरी यात्रा, कॉमेडी और त्रासदी जो जीवन है और घर और परिवार के लिए एक पुरानी यादों के माध्यम से ले जाएगा। इंतजार खत्म हुआ, डंकीड्रॉप4 - आउट नाउ।' फिल्म राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और एसआरके और गौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। यह राजकुमार हिरानी के साथ एसआरके का पहला प्रोजेक्ट है। फिल्म में शाहरुख खान और तापसी पन्नू के अलावा बोमन ईरानी और विक्की कौशल भी हैं।

तृप्ति डिमरी एक्टिंग के साथ घुमक्कड़ भी

एनिमल एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने फिल्म में अपने अभिनय से कई लोगों को प्रभावित किया है। यहां उनके यात्रा ब्लॉगों से उनकी कुछ स्पष्ट तस्वीरें देख रहे हैं। रणबीर कपूर की नई फिल्म एनिमल कई कारणों से सुर्खियों में बनी हुई है।

एनिमल एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने फिल्म में अपने अभिनय से कई लोगों को प्रभावित किया है। यहां उनके यात्रा ब्लॉगों से उनकी कुछ स्पष्ट तस्वीरें देख रहे हैं। रणबीर कपूर की नई फिल्म एनिमल कई कारणों से सुर्खियों में बनी हुई है। उनके ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक, प्रशंसक एनिमल के दीवाने हैं। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और अन्य प्रमुख सितारों के अलावा, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया है। फिल्म में उनकी एक्टिंग और बोल्ड सीन चर्चा का विषय बन गए हैं। जैसा कि अभिनेत्री सुर्खियों में रहती है, यहां उनकी यात्रा डायरी से उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखें जो आपको भटकने के लिए प्रेरित करेंगी।

तृप्ति डिमरी के इंस्टाग्राम पेज पर स्क्रॉल करें और आपको कुछ बहुत सुंदर यात्रा तस्वीरें दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि वह एक ट्रैकिंग प्रेमी है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से, तंबू में आराम करते हुए और भी बहुत कुछ उसकी कई तस्वीरें हैं। ग्रीस को यात्रा प्रेमियों के लिए सबसे पसंदीदा छुट्टियाँ बिताने की जगहों में से एक माना जाता है। यहां तृप्ति आपके अगले ग्रीस अवकाश के लिए कुछ फैशन लक्ष्य निर्धारित कर रही है। ऐसा लगता है कि तृप्ति डिमरी को यूरोप के अल्बानिया में सबसे ज्यादा आनंद आया जहां वह खूबसूरत समुद्र में नौकायन करने गईं। वह भव्य पृष्ठभूमि की तरह ही सुंदर दिखती है। एनिमल अभिनेत्री निश्चित रूप से जानती है कि समुद्र तट पर छुट्टियों के लिए कैसे बेहतरीन कपड़े पहनने हैं। वह इस हाई-स्लिट ड्रेस में तापमान बढ़ा रही है।

हमारा देश हमारा अभिमान

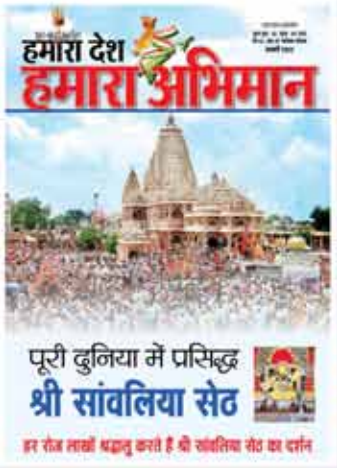

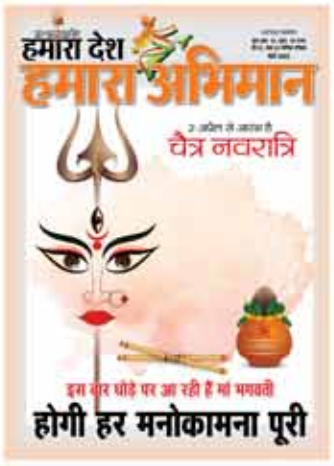

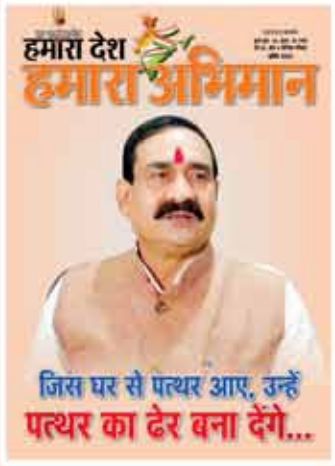

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं।

अर्थ : हे मोक्षरूप, विभु, व्यापक ब्रह्म, वेदस्वरूप ईशानदिशा के ईश्वर और हम सबके स्वामी शिवजी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित, चेतन, इच्छा रहित, भेद रहित, आकाश रूप शिवजी मैं आपको हमेशा भजता हूँ।